आरएनआई - एमपीएचआईएन/2021/81650

इंदौर, बुधवार 05 अगस्त 2026
■ वर्ष : 5 ■ अंक : 240
■ पृष्ठ : 6 ■ मूल्य : 2
dainikindoresanket.com
dainikindoresanket
dainikindoresanket
dainikindoresanket24@gmail.com

सांध्य दैनिक
इंदौर संकेत

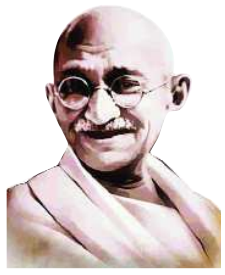

राष्ट्रपिता को नमन...

अंदर के पन्नों पर...

कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति को लेकर भाजपा ने किया तीखा हमला

पेज-2

मिर्जापुर : दि मूवी का पहला गाना 'दो नंबरी' रिलीज

पेज-5

अफसरों से पटरी बैठाना मेरा काम नहीं

पेज-6

न्यूज ब्रीफ

- CJP प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद में विपक्ष का विरोध मार्च
- तेलंगाना : कैश-फॉर-वोट केस में CM रेवंत रेड्डी को विदेश दौरे की मंजूरी
- रूस के मिसाइल-ड्रोन हमले में कीव में 15 लोगों की मौत
- उत्तर प्रदेश : अयोध्या में राम दरबार दर्शन के लिए पास व्यवस्था खत्म
- 2027 चुनाव के तैयारियों में जुटे अखिलेश यादव, आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी का बड़ा कार्यक्रम
- ई20 पेट्रोल पर राज्यसभा में चर्चा की मांग, संजय सिंह का नियम 267 नोटिस
- अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल : JXK में विरोध और जश्न, हाई अलर्ट
- कांग्रेस सांसद मणिक?कम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया
- पंजाब : अमृतसर पुलिस ने I.S.I समर्थित दो आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़, 9 गिरफ्तार

पीएम की सलाह पर मध्यप्रदेश में सीएम ने मारी बाजी

इंस्टाग्राम पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 20 लाख फॉलोअर्स मंत्री विजय शाह के सबसे कम 3,924 फॉलोअर्स

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल ● देश की राजनीति में अब सोशल मीडिया सिर्फ प्रचार का माध्यम नहीं, बल्कि जनता तक सीधी पहुंच का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केंद्रीय मंत्रियों को इंस्टाग्राम पर सक्रियता बढ़ाने और रील्स-शॉर्ट वीडियो के जरिए युवाओं तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने की सलाह दी।

सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद पाया गया कि जहां कुछ मंत्री लाखों फॉलोअर्स के साथ डिजिटल दुनिया में मजबूत मौजूदगी रखते हैं, वहीं

कई मंत्री ऐसे भी हैं जिनके फॉलोअर्स की संख्या 10 हजार से भी कम है।

मोहन कैबिनेट के टॉप-5 इंस्टाग्राम स्टार : मध्य प्रदेश के सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 20 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ सबसे आगे हैं। मंत्रियों में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय 7.44 लाख फॉलोअर्स के साथ पहले स्थान पर हैं। उनके बाद सहकारिता एवं खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग 3.84 लाख, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल 1.77 लाख और उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला 1.55 लाख फॉलोअर्स के साथ क्रमश: दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर हैं।

कई मंत्री अब भी हजारों फॉलोअर्स तक सीमित : जहां सरकार के प्रमुख चेहरे सोशल मीडिया पर लाखों लोगों से जुड़े हैं, वहीं कई मंत्रियों की डिजिटल पहुंच अब भी सीमित है। सबसे कम फॉलोअर्स कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह के हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर केवल 3,924 फॉलोअर्स हैं।

दतिया उपचुनाव मामले को लेकर मुख्यमंत्री आवास में दो घंटे तक चली बैठकों

आशुतोष ने दिए भितरघात के सबूत अभी और नेताओं पर गिरेगी गाज

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल ● दतिया उपचुनाव में मिली हार के बाद भाजपा सकते में हैं। आधा दर्जन मंत्रियों समेत करीब सवा सौ प्रदेश स्तरीय नेताओं को मैदान में उतारने के बाद भी उसे छह हजार से अधिक मतों से हार मिली है। हार को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास में दो घंटे से अधिक समय तक बैठक चली।

बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, आधा दर्जन से अधिक मंत्री और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ उपचुनाव हारे आशुतोष तिवारी भी मौजूद थे। बताया जाता है कि आशुतोष ने सीएम और संगठन नेताओं को भितरघात के संबंध में आडियो रिकार्डिंग समेत कई अन्य

डिजिटल और दस्तावेजी सबूत भी सौंपे। बैठक में दतिया के स्थानीय नेताओं समेत डेढ़ दर्जन से अधिक पार्षदों की भूमिका पर भी सवाल उठे। इन पर भी गाज गिरना तय मानी जा रही है। दतिया में इस बार भाजपा ने स्थापित नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट कर उनकी जगह संगठन से सालों से जुड़े रहे आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा था। पार्टी ने यहां अपनी पूरी ताकत भी झोंकी पर उसे सफलता नहीं मिल पाई।

भाजपा अब इस हार को केवल एक उपचुनाव का परिणाम नहीं, बल्कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव से पहले संगठन को कसने के अवसर के रूप में देख रही है। पार्टी नेतृत्व का संदेश साफ है कि संगठनात्मक अनुशासन से समझौता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ताकि निकाय चुनाव में पार्टी लाइन से हटकर काम करने की पुनरावृत्ति न हो। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, उपचुनाव प्रभारी भारत सिंह कुशवाह, प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी, डिप्टी सीएम देवड़ा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राव उदय प्रताप सिंह, राकेश शुक्ला समेत संगठन और सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे।

बड़ा फैसला : बिना इंश्योरेंस अब नहीं मिल पाएगा पेट्रोल

नई कारों का थर्ड पार्टी बीमा 4 साल और बाइक के लिए 6 साल का लेना अनिवार्य

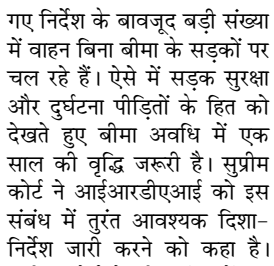

नई दिल्ली (एजेंसी) ● गाड़ियों के इंश्योरेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने आईआरडीएआई को नई वाहनों के लिए अनिवार्य थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस की अवधि बढ़ाने का निर्देश दिया है।

अब नई कारों के लिए थर्ड पार्टी बीमा 3 साल की जगह 4 साल और नए दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल की जगह 6 साल का लेना अनिवार्य होगा। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की पीठ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने दिया है। कोर्ट ने बिना बीमा के सड़कों पर चल रहे वाहनों को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि साल 2018 में दिए गए निर्देश के बावजूद बड़ी संख्या में वाहन बिना बीमा के सड़कों पर चल रहे हैं। ऐसे में सड़क सुरक्षा और दुर्घटना पीड़ितों के हित को देखते हुए बीमा अवधि में एक साल की वृद्धि जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने आईआरडीएआई को इस संबंध में तुरंत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीमा नियमों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करने के लिए आईआरडीएआई को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि बीमा की चेकिंग के लिए हाईवे और सड़कों पर लगे ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरों को बीमा डेटाबेस और बाहन पोर्टल से जोड़ा जाए।

कांग्रेस का दिल्ली में मंथन

कई जिलाध्यक्षों पर गिर सकती है गाज

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल ● आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मध्यप्रदेश कांग्रेस अब संगठन को और मजबूत बनाने की कवायद में जुट गई है। इसी सिलसिले में मंगलवार को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश संगठन की अहम समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जिलाध्यक्षों के कामकाज का विस्तृत आकलन किया। बैठक में संगठन सृजन अभियान के तहत पिछले वर्ष नियुक्त किए गए जिलाध्यक्षों के प्रदर्शन, संगठन विस्तार, बूथ स्तर की सक्रियता, सदस्यता अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम और जनआंदोलनों में भागीदारी की समीक्षा की गई। सूत्रों के अनुसार, कमजोर प्रदर्शन

करने वाले कई जिलाध्यक्षों के कामकाज पर गंभीर चर्चा हुई और आने वाले दिनों में कुछ पर कार्रवाई की हो सकती है।

तीन श्रेणियों में तैयार हुआ रिपोर्ट कार्ड-सूत्रों के मुताबिक, जिलाध्यक्षों को ए, बी और सी श्रेणी में बांटकर समीक्षा की जा रही है। ए श्रेणी में पांच ऐसे जिलाध्यक्ष शामिल हैं, जिनके संगठनात्मक कामकाज को सबसे बेहतर माना गया है। बी श्रेणी में 45 जिलाध्यक्षों को रखा गया है। मंगलवार को इन्हीं जिलाध्यक्षों के कामकाज की समीक्षा की गई। संगठन की मजबूती, जनसंपर्क, बूथ प्रबंधन और पार्टी गतिविधियों को लेकर उनसे चर्चा की गई। सी श्रेणी में शामिल 15 जिलाध्यक्षों की समीक्षा बुधवार को होगी। इन जिलों में संगठन की स्थिति पर विशेष मंथन किया जाएगा।

मानसिक चिकित्सालय : दो साल का प्रोजेक्ट, चार साल बाद भी अधूरा

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● मध्य प्रदेश का पहला सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ का निर्माण कार्य अधर में लटक गया है। बाणगंगा स्थित मानसिक चिकित्सालय में 22 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से तैयार हो रहा यह प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा होना था, लेकिन 4 साल का समय बीत जाने के बाद भी यह अधूरा पड़ा है। अंतिम चरण में पहुंचे इसके निर्माण कार्य पर रिवाइज्ड एस्टीमेट की स्वीकृति, लगभग 2 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट और फंड की कमी के कारण एक बार फिर ब्रेक लग चुका है। इससे पूर्व भी भुगतान और फंड की कमी के चलते यह प्रोजेक्ट 3 बार ठप हो चुका है।

इस प्रोजेक्ट के टेंडर पीडब्ल्यूडी की प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन यूनिट (पीआईयू)

के माध्यम से जारी किए गए थे, जिसकी कुल लागत 22 करोड़ 23 लाख रुपए तय हुई थी। भोपाल की एक एजेंसी ने 23 प्रतिशत कम दर पर लगभग 17.5 करोड़ रुपए में इसका ठेका लिया था। निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 24 महीने की समय-सीमा तय की गई थी, परंतु फंड जारी होने में लगातार हो रही देरी के कारण 48 महीने बीत जाने पर भी काम पूरा नहीं हो सका है। शुरुआत में बिजली की एलटी लाइन शिफ्ट करने में हुई देरी से 3-4 महीने काम रुका रहा। इसके उपरांत भुगतान में देरी के चलते 2 बार लंबे समय तक निर्माण बंद रहा, जिसके संबंध में पीआईयू अधिकारियों ने लगातार पत्राचार किया। एजेंसी को बकाया राशि का भुगतान होने के उपरांत कुछ महीने पहले ही कार्य पुन: प्रारंभ हुआ था।

आरटीओ के धन कुबेर पूर्व कांस्टेबल शर्मा को जमानत

10 लाख के मुचलके पर मिली राहत

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने चर्चित आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत दे दी है। जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की सिंगल बैंच ने 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहाई का आदेश दिया।

सौरभ शर्मा पर आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। जिला अदालत और फिर हाई कोर्ट पहले नियमित जमानत खारिज कर चुके थे। पत्नी की बीमारी के आधार पर मांगी गई अंतरिम जमानत भी नहीं मिली थी। इसके बाद सौरभ ने बदली परिस्थितियों का हवाला देकर तीसरी नियमित जमानत याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने लंबी हिरासत और ट्रायल में देरी को देखते हुए अब नियमित जमानत दे दी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने चर्चित आरटीओ पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा को नियमित जमानत दे दी है। जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की एकल पीठ ने 31 जुलाई को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। यह आदेश 4 अगस्त को शाम करीब छह बजे अपलोड हुआ। अदालत ने सौरभ को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की स्थानीय जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

पहले दो बार नहीं मिली थी राहत

सौरभ शर्मा की नियमित जमानत पहले जिला अदालत ने खारिज की थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने भी पहली नियमित जमानत याचिका मेरिट पर खारिज कर दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया। वहां से याचिका वापस लेते हुए कानून के अनुसार दोबारा आवेदन की छूट मिली थी।

गौतम पार्क कॉलोनी का सेल्समेन ग्राहकों के साथ कर रहा धोखाधड़ी

कॉलोनी के प्रबंधक कलेक्टर कार्यालय से 2 दिन में नामांतरण कराने का कर रहे खुलेआम दावा

निलेश चौहान : 94250-77209

देपालपुर ● दैनिक इंदौर संकेत

गौतमपुरा की गौतम पार्क कॉलोनी के रोज-रोज नए-नए खेल लगातार उजागर हो रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं से वंचित कॉलोनी ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर प्लाट बेचने का काम कर रही है। आए दिन नए-नए धमाके और मानसून ऑफर निकाल कर ग्राहकों को इसके जाल में फसाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पहले जिन ग्राहकों को प्लाट बेचे गए वह नामांतरण के लिए दर-दर भटक रहे हैं इस कॉलोनी के डेवलपमेंट में हरीश चौधरी, रियाज पटेल, और लव पाल के नाम सामने आए हैं। जिन्होंने ग्राहकों को पप्लाट तो दिए लेकिन जमीन पर मूलभूत सुविधाएं आज तक ग्राहकों को नहीं मिली है। उसके बावजूद भी मानसून ऑफर के नाम पर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने में कॉलोनाइजर बाज नहीं आ रहे हैं। ग्राहकों को बड़े-बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं।मध्यम वर्ग परिवार एक-एक रूपये की पूंजी जमा कर अपने लिए आशियाना बनता है। लेकिन ऐसे धोखेबाज उन्हें अपने जाल में फंसा कर जीवन के सारी पूंजी बर्बाद करने को मजबूर कर देते हैं।

गौतम पार्क कॉलोनी का सेल्समेन ग्राहक को प्लाट खरीदने के बाद 2 दिन में नामांतरण करवाने का वादा कर रहा है। लेकिन सेल्समैन को यह मालूम नहीं कि इस कॉलोनी का 22 लाख रुपए से अधिक टैक्स नगर परिषद गौतमपुरा में बकाया है। जिसकी वसूली के नगर परिषद ने कहीं बार नोटिस जारी किए हैं उसके बावजूद भी कॉलोनाइजर ने नगर परिषद का भुगतान नहीं किया है। इतना ही नहीं सेल्समैन ने यह भी कहा नामांतरण हम कलेक्टर से कर कर देंगे आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है नामांतरण का पूरा काम हमारी सेटिंग से होगा। यह बात सेल्समेन और ग्राहक के बीच में फोन पर हुई जिसके प्रमाण ग्राहक के पास

मौजूद है।

सेल्समेन ने ग्राहकों से कहा प्लाट आप अभी ले लो बिजली आने में 2 महीने लगेंगे क्योंकि इस कॉलोनी में बिजली को लेकर चोरी के केस बने हुए हैं। कॉलोनी में ट्रांसफार्मर लगा है लेकिन एक लाख रु से अधिक राशि बिजली विभाग की बकाया है। कॉलोनाइजर इस मामले की सेटिंग बिजली विभाग के अधिकारियों से बिठाने में लगा है लेकिन सूत्र बताते हैं कि लिफाफे के दम पर अधिकारियों के समक्ष कॉलोनाइजर की सेटिंग नहीं जमी इसलिए अब प्लाट धारको को सेल्समेन कह रहा है। कॉलोनी में बिजली के लिए दो महीने का इंतजार करना होगा। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है। कि कॉलोनाइजर सिर्फ अपना माल खपाने में लगा है आम जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे कॉलोनाइजर को कोई लेना-देना नहीं है। जैसे तैसे ग्राहकों को प्लांट बेचकर कॉलोनाइजर फ्री होना चाहता है।

नाम नहीं छापने की शर्त पर एक पीड़ित ने बताया कि में नामांतरण के लिए एक महीने से कॉलोनी के चक्कर लग रहा हूं मैंने मकान भी बना लिया लेकिन अभी तक मेरा नामांतरण नहीं किया गया यह प्लाट मैने कॉलोनी का मेंटेनेंस देख रहे लव पाल के रिश्तेदार से लिया था मेरी ओर से उनका पूरा भुगतान भी कर दिया लेकिन उसके बावजूद भी मेरा नामांतरण नहीं करवा रहे हैं जानकारी में यह भी पता चला जो प्लाट लव पाल के रिश्तेदार ने बेचा उस पर उन्होंने पहले ही लोन ले रखा है जिसका भुगतान आज तक नहीं किया मेरे साथ खुलेआम धोखाधड़ी हुई है मे इस मामले की शिकायत कॉलोनी सेल की अधिकारी रोशनी पाटीदार के समक्ष करूंगा जरूरत पड़ी तो इस मामले में कलेक्टर शिवम वर्मा से भी बात करुंगा।

न्यूज ब्रीफ

स्कूल प्रबंधन को लेकर वैश्य समाज में रोष

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● विगत दिनों वैश्य समाज के एक बंधु के बच्चे के साथ हुई घटना पर स्कूल प्रबंधन का नकारात्मक रवैया सामने आया था जिसके खिलाफ कई दिनों से पालक परेशान हो रहे थे? इसके खिलाफ वैश्य महासम्मेलन जिला इंदौर ने अपनी आवाज बुलंद की और विरोध प्रदर्शन करते ही स्कूल प्रबंधन हरकत में आ गया और विगत 15 दिनों से आँख मूंद कर बैठने वाले स्कूल प्रबंधन ने लिखित में आश्वासन देकर मामले का पटाक्षेप किया! धीरज खंडेलवाल के मार्गदर्शन में और जिला अध्यक्ष अशोक खंडेलवाल के नेतृत्व में अजय सोडाणी, हरीश विजयवर्गीय, निलेश अग्रवाल, नितिन माहेश्वरी, एडवोकेट राजेश खंडेलवाल, एडवोकेट हर्ष मेहता, पंकज अग्रवाल, संजय विजयवर्गीय, पंकज बूब,सहित कई वैश्य बंधुओं ने सहभागिता कर स्कूल प्रबंधन पर त्वरित निर्णय लेने के लिए दबाव बनाया!

बोल्ट 25 अगस्त को लॉन्च करेगा इवो और एस 5 जी स्मार्टफोन

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● बोल्ट जो कि फायर-बोल्ट का होमग्रोन स्मार्टफोन ब्रांड है ने आज अपने बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन्स - इवो और ऐस 5 जी के आगामी लॉन्च की आधिकारिक घोषणा की है, जो कि 25 अगस्त, 2026 को लॉन्च किए जाएंगे। ब्रांड ने फ्रीडम सेल 2026 के लिए फ्लिपकार्ट के साथ टाइटल स्पॉन्सर के रूप में अपनी रणनीतिक साझेदारी का भी खुलासा किया। हालाँकि, इन स्मार्टफोन्स की आधिकारिक लॉन्चिंग इस महीने के आखिर में होगी, लेकिन बोल्ट इस स्पॉन्सरशिप के जरिए प्रोडक्ट लॉन्च से पहले ही देशभर में मजबूत जागरूकता और ब्रांड पहचान बनाना चाहता है।

पार्टनर्स को किया सम्मानित

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● जापान के ब्रिजस्टोन कॉरपोरेशन की ग्रुप कंपनी ब्रिजस्टोन इंडिया ने 30 साल पहले भारत में परिचालन की शुरुआत की थी। ब्रिजस्टोन कॉरपोरेशन ने अपनी स्थापना के समय से ही विदेश में अपने कारोबार को विस्तार देने पर फोकस किया है। इस कार्यक्रम में वैश्विक स्तर पर अग्रणी ऑटोमोटिव मैन्यूफैक्चरर्स, सप्लायर पार्टनर्स, इंडस्ट्री लीडर्स और प्रतिष्ठित सरकारी प्रतिनिधि एक मंच पर आए। सभी संबंधित लोगों को लंबी साझेदारी और ब्रिजस्टोन में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। इसकी शुरुआत एशियाई बाजार में कदम रखने से हुई थी। आज के समय में कंपनी दुनियाभर के 150 से ज्यादा देशों में हाई-क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है और स्थानीयता के अनुरूप कारोबारी इकाइयों को स्थापित करने की दिशा में प्रयासरत है।

निर्माण की धीमी गति पर नाराजगी, एजेंसी पर जुर्माना

नगर निगम आयुक्त ने शहर की विभिन्न निर्माणाधीन सड़कों का किया निरीक्षण

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● शहर में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की धीमी रफ्तार पर नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने विभिन्न निर्माणाधीन सड़कों का निरीक्षण कर संबंधित एजेंसियों को तय समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। गुटकेश्वर मंदिर से सदर बाजार रोड तक निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर संबंधित एजेंसी पर नियमानुसार पेनल्टी लगाने के निर्देश भी जारी किए। आयुक्त ने मधुमिलन चौराहा-छावनी चौराहा, चंद्रभागा-हरसिद्धि, कलालकुई मस्जिद चंद्रभागा, मल्हारगंज-जिंसी चौराहा (लक्ष्मी प्रतिमा) तथा गुटकेश्वर मंदिर-सदर बाजार रोड तक चल रहे सड़क निर्माण कार्यों का मौके पर जाकर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों और कंसल्टेंट से कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। विशेष रूप से गुटकेश्वर मंदिर से सदर बाजार रोड तक सड़क निर्माण की प्रगति अपेक्षा से काफी धीमी मिलने पर आयुक्त ने अपर आयुक्त को संबंधित एजेंसी पर नियमानुसार आर्थिक दंड (पेनल्टी) लगाने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को निर्माण कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करने और कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए कहा।

यह रहे उपस्थित- निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर, कार्यपालन यंत्री ओपी कुशवाह, नरेश जायसवाल, क्षेत्रीय जोनल अधिकारी, निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि, कंसल्टेंट तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि शहर के विकास कार्य तय समय पर पूरे हों, इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग जारी रहेगी।

कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति को लेकर भाजपा ने किया तीखा हमला

शहर अध्यक्ष का व्यवहार गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्ति जैसा - सुमित मिश्रा

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● इंदौर की सियासत में कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति को लेकर भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष का व्यवहार किसी राजनीतिक दल के जिम्मेदार पदाधिकारी जैसा नहीं, बल्कि गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्ति जैसा है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस और शहर कांग्रेस में 'ड्रगिस्ट' और 'गुंडिस्ट' का गठबंधन दिखाई दे रहा है।

दरअसल, भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा मंगलवार को एक आयोजन में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस के अंदर चल रही कथित खींचतान को लेकर कई आरोप लगाए।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर नेताओं के बीच विवाद की जानकारी शहर में चर्चा का विषय है। पप्पू की कांग्रेस में जीतू के घर चिंटू और पिंटू का झगड़ा हुआ और दीपू ने उसमें बीच-बचाव किया। शहर में इस बात की जानकारी है।'

'ड्रगिस्ट और गुंडिस्ट का गठबंधन'-एक सवाल के जवाब में भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष यहां गुंडागर्दी कर रहे हैं, जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ड्रग माफियाओं से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा, 'एक तरफ ड्रगिस्ट और एक तरफ गुंडिस्ट हैं। इस तरह का गठबंधन शहर कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस में दिखाई पड़ रहा है। यह अजब-गजब का गठबंधन है।'

स्टेरॉयड लेने का भी आरोप-सुमित मिश्रा ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे पर स्टेरॉयड लेने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष के करीबियों से जानकारी मिली है कि वह सुबह-सुबह जिम जाते हैं और स्टेरॉयड की गोलियां खाते हैं। मिश्रा ने दावा किया कि दिनभर इसका प्रभाव रहता है, इसलिए वह चलते-फिरते लोगों से झगड़ा करते हैं।

कभी मारपीट करते हैं, कभी अपशब्द कहते हैं

भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चिंटू चौकसे कभी कांग्रेस के शहर कार्यालय में किसी कार्यकर्ता के साथ मारपीट करते हैं तो कभी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को अपशब्द कहते हैं। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के घर पर पार्टी नेताओं के बीच हुए विवाद का भी जिक्र किया। आरोप लगाया कि इस विवाद में एक नेता को कमरे में बंद कर पीटा गया और अवैध पिस्टल दिखाकर धमकाने जैसी घटनाएं हुईं। सुमित मिश्रा ने कहा कि यह घटना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर हुई थी, इसलिए इसके लिए किसी अतिरिक्त सबूत की जरूरत नहीं थी। इसके बावजूद न तो कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई और न ही कोई ठोस कदम उठाया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं का अपमान आखिर कब तक सहन करती रहेगी।

सांवेर में मना दतिया जीत का जश्न

दैनिक इंदौर संकेत

सांवेर ● मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में दतिया विधानसभा की शानदार जीत पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े के नेतृत्व में सांवेर मेंन चौराहे पर आतिशबाजी कर मिठाई वितरित की गई पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष श्याम सोनी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव विक्रम चौधरी मनोहर सिंह बडोदिया खान राजेंद्र व्यास भारत सिंह पंचोला पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष फखरुद्दीन काजी, ईसाक खान, रफीक अली कालू, शंकर परमार, जीतू सिसोदिया राजेश जसोदिया,कमलेश पटेल, सुधीर राव, मनोहर सिंह हिंडोलिया, पिंटू मंडलोई शाहिद अनेक कांग्रेसियों ने जमकर आतिशबाजी की और मिठाई से एक दूसरे का मुंह मीठा कराया, इस अवसर पर पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष श्याम सोनी ने कहा कि जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठ को अब समझ चुकी है इनका काला चेहरा बेनकाब हो गया है दतिया से शुरू हुआ जीत का सिलसिला अब कांग्रेस की सरकार तक निरंतर चलता रहेगा।

अगस्त और सितंबर की राशन सामग्री का एकमुश्त वितरण 31 अगस्त तक

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों से अगस्त एवं सितम्बर की राशन सामग्री का एकमुश्त वितरण 31 अगस्त तक करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गये हैं। उन्होंने कहा है कि राशन सामग्री का शत् प्रतिशत उठाव 15 अगस्त तक पूरा कर उचित मूल्य दुकानों में भण्डारण सुनिश्चित किया जाए।

अन्त्योदय अन्न योजना के हितग्राहियों को 35 कि.ग्रा. प्रति परिवार राशन (गेहूँ, चावल) एवं प्राथमिकता परिवार श्रेणी में आने वाले हितग्राहिओं को 5 कि.ग्रा. प्रति सदस्य राशन दिया जाता है। साथ ही दोनों श्रेणी के हितग्राहियों को एक कि.ग्रा. नमक प्रति परिवार दिया जाता है। पीओएस मशीन में अगस्त एवं सितम्बर की राशन सामग्री को वितरित करते समय दो बार बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के अनुबंधित परिवहनकर्ताओं के माध्यम से दुकानों पर राशन सामग्री का प्रदाय समय पर सुनिश्चित करायें। इसकी जीपीएस के माध्यम से मॉनिटरिंग भी करें। उचित मूल्य दुकानों पर राशन सामग्री प्रदाय एवं वितरण की नियमित मॉनिटरिंग करने और इसमें किसी भी प्रकार की अनियमित्ता पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये गये हैं।

युवाओं की भागीदारी से 9 अगस्त को निकलेगी भव्य तिरंगा यात्रा- मुख्यमंत्री

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अगस्त आज़ादी का पर्व मनाने का महीना है। हम सब हर्षोल्लास से स्वतंत्रता दिवस मनाएं। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाए। इस दिन भोपाल में नागरिकों और युवाओं के सहयोग से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाए। यह तिरंगा यात्रा समाज में अपनी आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने की प्रेरणा सहित देशभक्ति की भावना के प्रसार का माध्यम बनेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोमवार को राज्य शूटिंग अकादमी भोपाल में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और विभागीय मैदानी गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में खेल एवं युवा कल्याण एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, मध्यप्रदेश युवा आयोग के अध्यक्ष प्रवीण शर्मा, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. सुदाम खाड़े, सचिव खेल संजीव सिंह, संचालक खेल अंशुमन यादव सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में कहा कि हमारे खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और कौशल से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में मध्यप्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। खिलाड़ियों के पोषण, प्रशिक्षण एवं उनके कौशल सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाए। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण में नवीन तकनीकों को अपनाया जाये। ओलम्पिक, एशियाड और राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाए।

कर्मठ शिक्षक रामस्वरूप गोमे ने जिस स्थान से सेवा शुरू की वहीं से सेवानिवृत्त हुए

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● समर्पित, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, सरल, सहज व्यक्तित्व के शिक्षक रामस्वरूप गोमे ने अपने नाम के अनुरूप राम जी के चरित्र और आचरण को अपने स्वरूप में उतारा है। जीवन के साढ़े तिरयालिस वर्ष उन्होंने अपने विद्यार्थियों एवं ग्रामवासियों को उत्कृष्ट सेवा करते हुए बिताए हैं। ऐसे शिक्षक बिरले ही होते हैं। उक्त उदगार वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन मप्र के प्रांतीय उपाध्यक्ष भगवतीप्रसाद पंडित ने गारी पीपल्या विद्यालय के सेवाभावी शिक्षक रामस्वरूप गोमे की सेवानिवृति के अवसर पर आयोजित बिदाई एवं अभिनन्दन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा जगत का अनोखा रिकार्ड होगा कि किसी शिक्षक ने एक ही शाला में पूरी सर्विस कर ली और कभी उसका ट्रांसफर नहीं हुआ।

भारत में पहली बार आएगी मॉड्यूलर प्लग फ्लो सीबीजी तकनीक

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● इन्फिस्टार रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड ने फिनलैंड की कंपनी आर्सीप्लग ओय के साथ एक विशेष जॉइंट वेंचर किया है। इस भागीदारी के तहत भारत के पहले मॉड्यूलर प्लग फ्लो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनाए जाएंगे। इस पहल को देश में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने और आधुनिक बायोगैस तकनीक उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। दोनों कंपनियों ने साझेदारी में आर्सीस्टार बायोएनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नामक नई कंपनी रची है। यह कंपनी 3 टन प्रतिदिन से कम क्षमता वाले मॉड्यूलर प्लग फ्लो सीबीजी प्लांट को तैयार करेगी। यह प्लांट कृषि अवशेष, नगर निगम के ठोस कचरे और अन्य जैविक कचरे से क्लीन एनर्जी का उत्पादन करेंगे।

सावधान! स्क्रॉलिंग है नया धूम्रपान, धीरे-धीरे खोखला कर रहा मानसिक स्वास्थ्य

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● जैसे एक ज़माने में धूम्रपान को कूल मानकर लोग अपने फेफड़ों को नुकसान पहुँचाते थे, ठीक वैसे ही आज बिना सोचे-समझने घंटों रील्स और फ़ीड्स स्क्रॉल करना सेहत का नया दुश्मन बन चुका है। धूम्रपान शरीर को अंदर से खोखला करता है, वहीं लगातार स्क्रॉलिंग युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और दिमागी शांति को धीरे-धीरे खत्म कर रही है । यह बात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ अमित सोलंकी ने एक कॉलेज(प्रेस्टीज कॉलेज) में आयोजित इंडक्शन प्रोग्राम डिजिटल डिटॉक्स एंड मेंटल हेल्थ टॉपिक पर आयोजित सेशन में कहीं ।

संभागायुक्त लक्षकार ने आईडीए के विकास कार्यों की समीक्षा की

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● संभागायुक्त भास्कर लक्षकार की अध्यक्षता में आज आईडीए के तकनीकी विभाग, नियोजन विभाग एवं संपदा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आईडीए के सीईओ डॉ. परीक्षित झाड़े, नगर नियोजक, अधिक्षण यंत्री एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में संभागायुक्त लक्षकार ने आईडीए के विभिन्न विभागों की प्रचलित योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट देखी और उसकी समीक्षा की।

महू में अवैध शराब कारोबार पर बड़ी कार्रवाई

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायत पर महू क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की गई। रहवासी क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित शराब बिक्री एवं अहातों की शिकायत मिलने पर एसडीएम राकेश परमार के मार्गदर्शन में प्रशासनिक दल ने मौके पर पहुंचकर संयुक्त अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान लगभग पाँच अवैध ढाबों एवं एक अहाते को जेसीबी मशीनों की सहायता से हटाया गया। अभियान के दौरान मौके से अवैध शराब का जखीरा जब्त किया गया तथा अवैध रूप से उपयोग किए जा रहे घरेलू गैस सिलेंडरों को भी कब्जे में लिया गया। संबंधित प्रकरणों में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभियान का नेतृत्व एसडीएम राकेश परमार एवं तहसीलदार विवेक सोनी ने किया। इस दौरान नायब तहसीलदार राधावल्लभ धाकड़, अनिल मेहता, दिलीप द्विवेदी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी महादेव मुवेल सहित राजस्व, पुलिस एवं संबंधित विभागों का अमला उपस्थित रहा। प्रशासन को जनसुनवाई में बालाजी धाम कॉलोनी के रहवासियों द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी कि कॉलोनी के मध्य लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार संचालित होने से क्षेत्र का वातावरण प्रभावित हो रहा है तथा आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

बिजली कंपनी के इंदौर सीई ने उपभोक्ताओं से की सीधी बात

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के मुख्य अभियंता राजेश जैन ने मंगलवार को राजमोहल्ला जोन का विस्तार से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लाभान्वित आवेदकों, उपभोक्ताओं से चर्चा कर योजना के तहत प्रदान की जा रही सेवाओं की जानकारी प्राप्त की गई। आवेदकों द्वारा सेवाओं के प्रति संतोष व्यक्त किया गया। निरीक्षण के दौरान राजस्व संबंधी गतिविधियों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। फ्यूज काल शिकायत निवारण, राजस्व संग्रहण गतिविधियों सहित अन्य परिचालन कार्यों का जायजा लिया गया। बिजली कंपनी के सीई जैन ने ऊर्जस संबंधित सभी सेवाएं निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से उपलब्ध कराने के कार्यपालन यंत्री शैलेन्द्र सिंह भदौरिया, जोन प्रभारी विशाल वर्मा को निर्देश दिए।

बिजली उपभोक्ता अनजान लिंक, मैसेज को पूरी तरह नजरंदाज करें

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं से अधिकृत संदेश पर ही ध्यान देने व अनजान मोबाइल नंबर से आए संदेशों, फाइल, वाट्सएप फाइल को लेकर अत्यंत सावधानी रखने की अपील की हैं। कंपनी ने कहा कि कंपनी वाट्सएपर बिल किसी नंबर की बजाए mppkvvcl indore नाम से और अधिकृत एसएमएस mpsebw-S नाम से भेजती हैं, इसी तरह के मैसेज पर ध्यान दिया जाए। अन्य नंबरों से आए मैसेज, वाट्सएप व APK फाइल को पूरी तरह फर्जी मानकर नजरंदाज किया जाए। फर्जी संदेश, लिंक, APK फाइल से आपका मोबाइल तुरंत हैक हो जाएगा, मोबाइल की कमांड फर्जी व्यक्तियों के पास तुरंत पहुंचा जाएगी, व आपका बैंक बैलेंस, डाटा चुरा लिया जाएगा। कंपनी ने सम्माननीय बिजली उपभोक्ताओं से सतर्क रहना का विनम्र निवेदन किया हैं। कंपनी ने कहा कि आप अपने बिजली बिल जोन , वितरण केंद्र, पेटीएम, फोन पे, गुगल पे, भारत पे, कंपनी वेबसाइट व एप के माध्यम से जमा कर सकते हैं। किसी नंबर विशेष पर कभी भी भुगतान नहीं किया जाए।

पश्चिमी रिंग रोड़ के किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए हेल्प डेस्क स्थापित

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● पश्चिमी रिंग रोड़ के प्रभावित किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण और अन्य सहायता के लिए विशेष दल का गठन किया गया है। साथ ही हेल्प डेस्क भी हातोद तहसील कार्यालय में स्थापित की गई है। हातोद क्षेत्र के अनुविभागीय राजस्व अधिकारी राजेश सिंह ने बताया कि इस दल में राजस्व विभाग, एनएचएआई तथा संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। हेल्प डेस्क में भी संबंधित विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। हेल्प डेस्क में हातोद तहसील अंतर्गत आने वाले प्रभावित ग्राम अरण्या, पालड़ी, मिर्जापुर, बडोदिया पंत, सिकंद्री, अकासोदा, कराड़िया, नाहरखेड़ा, जिन्दाखेड़ा, जंबुड़ी सरवर, अजनोटी और मांगलिया अरण्या शामिल है।

गुणवत्तापूर्ण, संस्कार आधारित शिक्षा राष्ट्र के विकास का आधार- पटेल

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण और संस्कार आधारित शिक्षा समाज और राष्ट्र के विकास का आधार है। विकसित भारत के लिए गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा अत्यंत ज़रूरत है। युवाओं के लिए कौशल, रोज़गार और संस्कार आधारित शिक्षा समय की माँग है। शिक्षा जगत के मनीषियों को देश के युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण और संस्कार आधारित शिक्षा पर विशेष चिंतन किया जाना चाहिए।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि हर बच्चे के लिए रोजगारपरक शिक्षा सुनिश्चित करना शिक्षा जगत की सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों को अधिक से अधिक रोज़गार और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों का संचालन करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट की व्यवस्था बनाये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उद्योगों की माँग के अनुरूप पाठ्यक्रमों को तैयार करें। शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक संस्थानों और प्रतिष्ठानों से समन्वय करें। और आवश्यकता अनुसार शोध और अनुसंधान कर नये कोर्स डिजाइन करें ।

सांध्य दैनिक
इंदौर संकेत
इंदौर, बुधवार 05 अगस्त 2026

न्यूज ब्रीफ

दीदीमाँ साध्वी ऋतुम्भरा देवी ने किया बाणेश्वरी कावड़ यात्रा में शामिल भक्तों का स्वागत

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • महेश्वर के अहिल्या घाट से सावन के पहले सोमवार को सुबह प्रारम्भ हुई इंदौर की विशाल बाणेश्वरी कावड़ यात्रा मंगलवार को गुजरी से मानपुर पहुँच गई। प्रख्यात साध्वी दीदीमाँ ऋतुम्भरा देवी, युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विप्लव जैन एवं पूर्व विधायक पांचीलाल मीणा ने यात्रा संयोजक एवं विधायक गोलू शुक्ला सहित सभी कावड यात्रियों को बधाई देते हुए सनातन धर्म की मजबूती के लिए किए जा रहे उनके सद्प्रयासों की खुलेमन से सराहना की। गुजरी से योग, प्राणायाम, पौधरोपण एवं पूजा-अर्चना के बाद प्रारम्भ हुई बाणेश्वरी कावड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का जोश दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। सुबह गुजरी फाटे पर दीदीमाँ साध्वी ऋतुम्भरा के पहुँचते ही श्रद्धालुओं का जोश उफान पर पहुँच गया।

भोले के भक्तों का मेला- अब तक 6 लाख बिल्व पत्रों से हो चुकी पूजा-अर्चना

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • पंचकुइया स्थित श्री भूतेश्वर महादेव मन्दिर पर चल रहे सर्व मनोकामना सिद्धिप्रद अहर्निश लक्ष्य बिल्वार्चन चिंतामणि महाप्रयोग में अब तक 6 लाख बिल्व पत्र समर्पित किए जा चुके हैं। इस आयोजन में देशभर से आए विद्वानों, आचार्यों और ब्राह्मणों के सानिध्य में प्रतिदिन 24 घंटे शास्त्रोक्त मंत्रोच्चार के बीच 1 लाख बिल्व पत्र से रुद्राभिषेक, रुद्रपाठ एवं शिव आराधना से समूचा पंचकुईया क्षेत्र गुंजायमान हो रहा है। भूतेश्वर महादेव मंदिर के प्रमुख पं. हरीशानंद तिवारी एवं पं. यतीन्द्र तिवारी ने बताया कि श्रावण के पहले दिन से यहाँ दिन-रात भक्तों का मेला जुट रहा है।

परस्पर गार्डन से सप्त नदियों का जल लेकर ढाई हजार समाज बंधु करेंगे अभिषेक

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • पश्चिमी मध्यप्रदेश प्रादेशिक माहेश्वरी सभा के तत्वावधान में संस्था माहेश्वरी कुटुम्ब द्वारा रविवार 9 अगस्त को सुबह 9 बजे से रिंग रोड स्थित परस्पर गार्डन परिसर से निकलने वाली 'जय महेश कावड़ यात्रा' में इस बार अनेक आकर्षण शामिल होंगे। यात्रा में देश की 7 प्रमुख नदियों के जल के साथ ही 6 झांकियां और लगभग ढाई हजार श्रद्धालु बोल बम और जय शिव का उद्घोष करते हुए शामिल होंगे। मंगलवार को संस्था के नवलखा स्थित कार्यालय पर आयोजित बैठक में कावड़ यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में माहेश्वरी कुटुम्ब के संस्थापक श्रीमती शारदा प्रकाश अजमेर सहित माहेश्वरी सभा एवं अन्य सहयोगी संगठनों की ओर से महेश मूंगड, अशोक इनानी, मनोज छापरवाल, पुष्प माहेश्वरी, अजय झंवर (सेंधवा), दिलीप लोया (उज्जैन), मधुसूदन भल्लिका, रुपेश भूतड़ा, राजेश मूंगड, सुरेश हेडा, श्रीमोहन सोमानी, गोपाल राठी एवं माहेश्वरी समाज के प्रमुख संगठनों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में यह निर्णय भी लिया गया कि यात्रा में शामिल सभी मातृशक्ति पीताम्बर एवं पुरुष भगवा धोती-कुर्ता या कुर्ता-पायजामा के परिधान में शामिल होंगे। यात्रा परस्पर गार्डन से प्रारम्भ होकर मेन रोड, फूटी कोठी चौराहा, रणजीत हनुमान, नाकोडा से गुमाश्ता नगर स्थित शिव मंदिर पहुंचेगी जहाँ शहर के गणमान्य जनप्रतिनिधियों एवं समाज के वरिष्ठजनों के मार्गदर्शन में समाज में एकता और सदभाव के लिए प्रार्थना भी की जाएगी।

डायरी, अलॉटमेंट व रजिस्ट्री के बाद भी नहीं मिली जमीन

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • शहर में जमीन के सौदों में धोखाधड़ी के मामलों में तमाम सख्ती भी बेअसर साबित हो रही है। भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने 2012, 2016, 2021 और 2023 में चार विशेष अभियान चलाए। सहकारी संस्थाओं की जांच हुई, भूमाफियाओं पर एफआईआर दर्ज हुई और गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुए। बिना रेरा अनुमति और डायरी पर प्लॉट बेचने वालों पर कार्रवाई भी हुई। इसके बावजूद भास्कर पड़ताल में ऐसे कई मामले सामने आए जिनमें डायरी पर पूरा भुगतान लेने, अलॉटमेंट लेटर देने और रजिस्ट्री करने के बाद भी खरीदारों को जमीन नहीं मिली।

भूमाफियाओं पर एफआईआर के बाद भी खरीदारों को नहीं मिले कब्जे

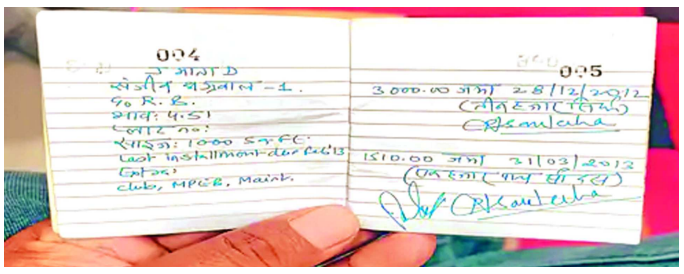

उधर, पुलिस कमिश्नर कार्यालय के सामुदायिक मध्यस्थता केंद्रों में जून 2024 से जुलाई 2026 के बीच जमीन विवाद के 1,062 प्रकरण पहुंचे। इनमें 475 मामलों में 6.70 करोड़ रुपए के समझौते हुए। जिला प्रशासन की जनसुनवाई में सितंबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच 12,227 आवेदन आए। इनमें 1 से 3 प्रतिशत शिकायतें जमीन और कॉलोनियों से जुड़ी थीं।

सिर्फ कागजों में अलॉट कर दिए प्लॉट 2011-12 में सुपर कॉरिडोर स्थित ब्लूमबर्ग टाउनशिप में डायरी पर प्लॉट बेचकर निवेशकों से पूरा भुगतान ले लिया गया। कॉलोनाइजर प्रफुल्ल सकलेचा ने डायरी में खरीदार का नाम, प्लॉट का आकार, दर, जमा राशि और कॉलोनाइजर के हस्ताक्षर दर्ज किए गए। कई खरीदारों को अलॉटमेंट लेटर भी जारी किए गए। मुंबई निवासी रवींद्र गुप्ता को 1000 वर्गफीट प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर मिला था। संजीव अग्रवाल और अभय कटारिया ने भी 1000-1000 वर्गफीट प्लॉट का पूरा भुगतान किया। पर उन्हें प्लॉट नहीं मिले।

ये अब तक भटक रहे, न पैसा मिला न जमीन

मुश्ताक खान- 2022 में सिरपुर स्थित गीता पैलेस में 750 वर्गफीट प्लॉट 25 लाख रुपए में खरीदा। पूरा भुगतान करने के बाद रजिस्ट्री के समय पता चला कि प्लॉट पहले ही किसी अन्य के नाम दर्ज हो चुका है।

संतोष पति सतीश खन्ना- करीब 20 वर्ष पहले उमरिया में 1600 वर्गफीट जमीन खरीदी। रजिस्ट्री के बावजूद आज तक कब्जा नहीं मिला। 79 वर्षीय विधवा महिला तीन बार जनसुनवाई में जा चुकी हैं।

अर्चना गर्ग- 1600 वर्गफीट जमीन खरीदी। बाद में पता चला कि परियोजना का रेरा पंजीयन ही नहीं था। कब्जा आज तक नहीं मिला।

4 साल इंदौर बेहाल

भाजपा परिषद के विकास के दावों की पोल खोलते पोस्टर पूरे शहर में लगाए गए

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल,गिरीश जोशी के नेतृत्व मांई शहर में भाजपा परिषद के चार वर्षों के कार्यकाल के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा '4 साल इंदौर बेहाल' अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर पोस्टर लगाए गए। अभियान का नेतृत्व विवेक खंडेलवाल एवं गिरीश जोशी ने किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महापौर लगातार चार वर्षों में अभूतपूर्व विकास के दावे करते रहे हैं, जबकि शहर की वास्तविक स्थिति इन दावों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। नसिया रोड से गुजराती स्कूल, जूनी इंदौर, चंद्रभागा, कलाकुई मस्जिद मार्ग सहित कई प्रमुख सड़कें लंबे समय से खुदी हुई या जर्जर हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इनमें से कुछ मार्गों पर कार्य वर्षों से अधूरा पड़ा है, जिससे आम नागरिकों, व्यापारियों, विद्यार्थियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि वास्तव में विकास हुआ है तो फिर शहर की प्रमुख

सड़कें बदहाल क्यों हैं? बरसात के मौसम में जगह-जगह गड्ढे, जलभराव और अधूरे निर्माण कार्य इंदौर की पहचान बनते जा रहे हैं। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद नागरिकों को अच्छी सड़कें और सुगम यातायात उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि '4 साल इंदौर बेहाल' अभियान किसी एक सड़क का नहीं, बल्कि पूरे शहर की बदहाल स्थिति का प्रतीक है। पोस्टरों के माध्यम से जनता का ध्यान उन समस्याओं की ओर आकर्षित किया जा रहा है जिनसे शहरवासी रोज़ाना जूझ रहे हैं।

इंदौर जिले में 7 अगस्त से शुरू होगा मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार 'मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026' के इंदौर जिले में 7 अगस्त से प्रारंभ होगा। अभियान का उद्देश्य आम नागरिकों तक शासन-प्रशासन की पहुंच को और अधिक सशक्त बनाना, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से समस्याओं का मौके पर निराकरण करना, शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करना तथा लोक सेवाओं का समय-सीमा में प्रदाय सुनिश्चित करना है। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा द्वारा अभियान के सफल संचालन के लिए विस्तृत आदेश जारी करते हुए 7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027 तक प्रत्येक शुक्रवार आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का कैलेंडर निर्धारित किया गया है। अभियान के तहत प्रत्येक शुक्रवार जिले के नगर निगम, नगर परिषद एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में जिला प्रशासन, स्थानीय निकायों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहकर आम नागरिकों की समस्याएं सुनेंगे और उनका यथासंभव मौके पर ही निराकरण करेंगे। साथ ही विकास कार्यों, शासकीय योजनाओं, लोक सेवा गारंटी से संबंधित सेवाओं एवं अन्य जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अभियान का नोडल अधिकारी बनाया गया है।

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले, जैविक उत्पादों की बिक्री के लिये ई-प्लेटफार्म सुनिश्चित किये जाये

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • संभागायुक्त भास्कर लक्षकार की अध्यक्षता में सोमवार को कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, मण्डी बोर्ड, मत्स्य विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, दुग्ध संघ, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण आदि विभागों की विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के संयुक्त संचालक, संयुक्त आयुक्त विकास श्रीमती शिवानी वर्मा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। संभागायुक्त श्री लक्षकार ने कहा कि यह वर्ष कृषि कल्याण वर्ष है। कृषि का रकबा बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए विशेष कार्ययोजना बनायी जाये। शासन की योजनाओं का लाभ सभी पात्र किसानों को मिले। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पात्र हितग्राही छूटे नहीं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाये। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादक को बढ़ावा देने के लिये राज्य शासन द्वारा चलायी जा रही डॉ. अम्बेडकर भीमराव कामधेनु योजना का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाये। जैविक उत्पाद की बिक्री के लिये ई-प्लेटफार्म सुनिश्चित किये जाये। अमानक उर्वरक एवं बीज की बिक्री करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाये। साथ ही भू-राजस्व की वसूली में तेजी लायी जाये। जे फार्मा एप में पंजीयन की कठिनाई को कैसे सरल बनाया जा सकता है, इस बारे में विशेष कार्ययोजना बनायें। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों को गंभीरता से लिया जाये तथा समयसीमा में प्रकरणों का निराकरण किया जाये।

संभागायुक्त लक्षकार ने कहा कि इंदौर संभाग में नरवाई प्रबंधन में सुदृढ़ता लायी जाये। किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन हेतु वैकल्पिक संसाधन एवं व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाये, उन्हें नरवाई जलाने के बजाय पर्यावरण अनुकूल उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। इन प्रयासों से संभाग में नरवाई जलाने की घटनाओं में कमी आयेगी। उन्होंने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में पात्र हितग्राहियों को जोड़ा जाये। उन्होंने कहा कि विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली को और सुदृढ़ किया जाये। उन्होंने कहा कि इंदौर सहकारी दुग्ध संघ अपने उत्पादों की बिक्री के लिये रिटेल आउटलेट की संख्या बढ़ायें। दूध उत्पादन की वृद्धि के लिये विशेष कार्ययोजना बनाएं। साथ ही मत्स्य उत्पादन की बिक्री के लिये स्मार्ट सिटी पार्लर बनाया जाये। मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने लिये ऐसे स्थान चिन्हित किया जाये, जहां बड़ी संख्या में खरीददार आते हैं। बैठक में बताया गया कि संभाग में फसल उपार्जन के लिये मण्डी बोर्ड की 16 मंडियां है। मंडियों एवं उप मंडियों में 10 टन से अधिक के कांटे लगाये गये हैं। मण्डी बोर्ड द्वारा फसलों का उपार्जन ई-प्रणाली किया हो रहा है।

विश्व जैन प्रसिद्ध गुणायतन के अधिष्ठाता बने बा.ब्र. अशोक भैया, उप-अधिष्ठाता बा. ब्र. अभय भैया

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर • जैन समाज के प्रमुख विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र गुणायतन में आज एक ऐतिहासिक घोषणा हुई। परम पूज्य गुरुदेव ने गुणायतन के सुचारू संचालन हेतु इंदौर उदासीन आश्रम के बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी को अधिष्ठाता एवं बाल ब्रह्मचारी अभय भैया को उप-अधिष्ठाता पद पर सुशोभित करने की घोषणा परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रमाण सागर जी के सानिध्य में गुणायतन ट्रस्टियों की उपस्थिति में करतल ध्वनि के साथ की गई। धर्म समाज प्रचारक राजेश जैन दद्दू ने बताया कि गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज ने अपने उद्बोधन ने कहा कि प्रतिष्ठा के बाद भी गुणायतन को संभालने के लिए त्यागी प्रतिनिधि की आवश्यकता है। 'त्यागियों के माध्यम से ही धर्म संस्थाएं टिकती हैं। अशोक भैया और अभय भैया का समर्पण, निष्ठा और सेवा भाव सर्वविदित है। हमने चाहा कि ये दोनों अपने प्रतिनिधि के रूप में यहाँ रहें, ताकि समाज को इनका संबल हमेशा मिलता रहे।' गुरुदेव के इन शब्दों पर पूरा सभागार करतल ध्वनि से गूंज उठा। भारत वर्षीय जैन समाज में हर्ष घोषणा के तुरंत बाद समाज के वरिष्ठजन, महिला-पुरुष श्रद्धालुओं ने खड़े होकर दोनों भैयाजी का अभिनंदन किया। इस उपलब्धि पर इंदौर दिगंबर जैन समाज के वरिष्ठ समाजसेवी डॉ जैनेन्द्र जैन महावीर ट्रस्ट के अध्यक्ष अमित कासलीवाल समाजिक सांसद के अध्यक्ष आनंद नवीन गोधा हंसमुख गांधी, श्रीमती पुष्पा कासलीवाल, श्रीमती मुक्ता जैन, साधना दगडे आदि ने बधाई दी।

हमें भारत में जन्म लेने का गर्व हर पल महसूस करते रहना चाहिए- सुधासागर म.सा.

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर •जिस देश में नींद सस्ती होती है वह देश सर्वश्रेष्ठ होता है। अमेरिका के लोग नींद की गोली खाकर सोते है इसलिए वो देश श्रेष्ठ नहीं हो सकता। हमारे भारत में तो व्यक्ति कभी भी कहीं भी बैठे-बैठे भी सुकून की नींद ले सकता है, इसीलिए अपना देश सर्वश्रेष्ठ है। अमेरिका में भले ही धन हो, शांति नहीं है। हमारे देश में शांति है इसलिए हमें भारत में जन्म लेने का गर्व हर पल महसूस करते रहना चाहिए। मन में यही भाव रखें कि हमारा प्रत्येक जन्म सिर्फ भारत में ही हो। संत शिरोमणि प.पू. विद्यासागर म.सा. परम प्रभावक शिष्य और राष्ट्रसंत मुनि पुंगव प.पू. श्री सुधासागर महाराज ने मंगलवार को सकल दिगम्बर जैन धर्म प्रभावना समिति के तत्वावधान में दलाल बाग के विशाल विद्या-सुधा सत्संग मंडप में आयोजित चातुर्मास की महती धर्मसभा में उपस्थित समाज बंधुओं को संबोधित करते हुए उक्त दिव्य और प्रेरक विचार व्यक्त किए। प्रवचन शुभारम्भ

के पूर्व चक्रवर्ती नवीन-शिवानी गोधा, सामाजिक संसद के अध्यक्ष आनंद-अंतिका गोधा परिवार द्वारा राष्ट्रदंत को शास्त्र भेंट किया गया। मनोज बज, यश, विजय और संजय पाटनी परिवार ने दीप प्रज्वलन किया। मंगलाचरण सुश्री रिद्धि बांझल ने किया।

प्रदेश के शिल्पकारों एवं बुनकरों के हितों की रक्षा हेतु मुख्यमंत्री सहित विभिन्न विभागों को ज्ञापन प्रेषित

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर •मध्य प्रदेश के पारंपरिक शिल्पकारों, बुनकरों एवं हस्तशिल्प से जुड़े परिवारों के हितों के संरक्षण, संवर्धन एवं आर्थिक सशक्तिकरण की मांग को लेकर हमीरचंद मंडलोई स्मृति लोक कल्याण संस्थान, इंदौर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन सहित विभिन्न विभागों, जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को विस्तृत ज्ञापन स्पीड पोस्ट तथा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया गया। संस्थान के संचालक एवं वरिष्ठ शिल्पकार भगवत (बबलू) मंडलोई ने बताया कि ज्ञापन में संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड को और अधिक सशक्त बनाने, निगम के संभावित निजीकरण अथवा पुनर्गठन संबंधी किसी भी

प्रस्ताव को निरस्त करने, पिछले लगभग तीन वर्षों से लंबित राज्य स्तरीय हस्तशिल्प पुरस्कार एवं विश्वकर्मा पुरस्कार की शीघ्र घोषणा करने तथा आगामी वर्षों के लिए पुरस्कार प्रक्रिया का वार्षिक कैलेंडर जारी करने की मांग की गई है।

सांध्य दैनिक
इंदौर संकेत
आपकी बात, इंदौर संकेत के साथ

डिजिटल रूप से लाखों पाठकों के साथ अपना नियमित संपर्क बनाते हुए दैनिक इंदौर संकेत अब एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आप भी अपने संस्थान, उत्पाद, संस्था का प्रचार-प्रसार दैनिक इंदौर संकेत के माध्यम से सकते हैं। इसके तहत आप चाहे प्रापर्टी व्यवसाय से जुड़े हैं या कोई बधाई संदेश देना है या जन्मदिन की शुभकामनाएं हो या कोई अन्य कैटेगरी में विज्ञापन देना चाहते हैं तो न्यूनतम दर पर प्रकाशित करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। दैनिक इंदौर संकेत संवेदनापूर्ण संदेशों को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। इसीलिए इस समाचार पत्र में शोक संदेश नि:शुल्क प्रकाशित किए जाएंगे।

कार्यालय का पता
5/6, राज मोहल्ला, महेश नगर,
गुरुद्वारे के सामने, इंदौर
संपर्क: 94250-64357, 94245-83000

सम्पादकीय

भारत में 20 हजार से ज्यादा अंग प्रत्यारोपण का नया रिकॉर्ड: फिर क्यों अधूरी है जीवन बचाने की मुहिम?

समाज में अंगदान को लेकर जो भ्रम बने हैं, उन्हें दूर करना होगा। साथ ही मानव अंगों की तस्करी एवं अवैध कारोबार पर भी पूरी तरह शिकंजा कसना होगा। अंगदान को महादान भी कहा जाता है, क्योंकि इससे जरूरतमंद लोगों को नया जीवन और उम्मीद की रोशनी मिलती है। यह समाज में मानवता, करुणा और परोपकार की भावना को मजबूत करता है। हाल के वर्षों में देश में अंगदान को लेकर जागरूकता बढ़ी है और इसी का नतीजा है कि पिछले साल 20 हजार से ज्यादा अंग प्रत्यारोपण हुए, जो अब तक के सर्वाधिक हैं। यही नहीं, देश में आधार-प्रमाणित अंगदान संकल्पों की संख्या भी पांच लाख से अधिक हो गई है। सरकार की ओर से बीते सोमवार को जारी किए गए ये आंकड़े मानव जीवन को बचाने के दृष्टिगत उत्साहजनक हैं, लेकिन मांग और उपलब्धता के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर बना हुआ है। इसमें एक बड़ी चुनौती मानव अंगों के अवैध कारोबार की भी है। हालांकि, इसके लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। इसके बावजूद अगर ऐसी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, तो जाहिर है कि इसके लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की लापरवाही भी जिम्मेदार है। यह सच है कि अंग प्रत्यारोपण की कुल संख्या के मामले में भारत अब अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि जीवित दाता से अंग प्रत्यारोपण में भी वह आगे है। वर्ष 2013 में देश में अंग प्रत्यारोपण कराने वालों की संख्या लगभग पांच हजार थी, जो 2025 में बढ़कर 20 हजार से अधिक हो गई है। यह संख्या दर्शाती है कि देश में अंगदान को लेकर आम लोगों में जागरूकता बढ़ी है। मगर मानव अंगों की मांग के मुकाबले उपलब्धता की दृष्टि से देखा जाए, तो यह आंकड़ा बेहद कम है। एक अनुमान के मुताबिक, देश में हर साल औसतन करीब पांच लाख लोगों को अंगों की जरूरत होती है, जबकि मृतक अंगदान की दर 10 लाख की आबादी पर एक से भी कम है। साफ है कि मांग और उपलब्धता के बीच संतुलन बनाने के लिए सरकार एवं समाज के स्तर पर लोगों को अंगदान के प्रति प्रोत्साहित करने के वास्ते विशेष अभियान और प्रयासों की जरूरत है। समाज में अंगदान को लेकर जो भ्रम बने हैं, उन्हें दूर करना होगा। साथ ही मानव अंगों की तस्करी एवं अवैध कारोबार पर भी पूरी तरह शिकंजा कसना होगा।

एफसीआरए और एनजीओः राष्ट्रीय सुरक्षा, डिजिटल पारदर्शिता और जवाबदेही का नया युग

किसी भी संप्रभु और लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए अपनी आंतरिक सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक ताने-बाने को बाहरी ताकतों के अवांछित प्रभाव से सुरक्षित रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। वैश्वीकरण के इस दौर में जहां पूंजी का सुगम प्रवाह सुनिश्चित हुआ है, वहीं विदेशी धन के जरिए देश की संप्रभुता को प्रभावित करने वाली आशंकाएं भी समानांतर रूप से बढ़ी हैं। भारत में विदेशी चंदे की निगरानी, नियमन और नियंत्रण के लिए 'विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम' यानी एफसीआरए एक मजबूत संवैधानिक और विनियामक ढाल के रूप में कार्य कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संचालित यह कानून समय और देश की सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ लगातार अधिक सुदृढ़ हुआ है। वर्ष 2026 में देश के विधायी और प्रशासनिक स्तर पर लागू किए गए ऐतिहासिक 'एफसीआरए संशोधन नियमों', नए पेश विधेयक और अत्याधुनिक डिजिटल सुधारों ने भारत में विदेशी फंडिंग के संचालन को पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह और राष्ट्रहित के अनुकूल बना दिया है। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में विदेशी पूंजी के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में प्रशासनिक सुगमता और डिजिटल गवर्नेंस को जोड़ते हुए एक बड़ी घटना सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' के मूल विजन को धरातल पर उतारते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जून 2026 को नई दिल्ली में अत्याधुनिक 'एफसीआरए 2.0 पोर्टल' को देश को समर्पित किया। राष्ट्रीय सरकारी क्लाउड 'मेघराज' पर पूरी तरह सुरक्षित तरीके से होस्ट किया गया यह नया संस्करण डिजिटल पारदर्शिता का एक अनूठा वैश्विक मानक स्थापित करता है। इस पोर्टल की शुरुआत के समय केंद्रीय गृह सचिव, विदेश सचिव और खुफिया ब्यूरो (IB) के महानिदेशक जैसी देश की शीर्ष सुरक्षा हस्तियों की उपस्थिति ने इसके रणनीतिक महत्व को रेखांकित किया था।

इस अत्याधुनिक तकनीकी सुधार के पीछे सरकार का प्राथमिक उद्देश्य देश के ईमानदार, पारदर्शी और वास्तविक रूप से राष्ट्र निर्माण में जुटे संगठनों के लिए विनियामक अनुपालन प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस, त्वरित और सुगम बनाना है। 'एफसीआरए 2.0 पोर्टल' के क्रियान्वयन से अब कागजी फाइलों की भौतिक प्रस्तुति की अनिवार्यता पूरी तरह समाप्त हो गई है। नए डिजिटल ढांचे में अत्याधुनिक आधार-आधारित प्रमाणीकरण, डिजिटल सिग्नेचर, और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन आधारित स्वचालित दस्तावेज़ विश्लेषण जैसी सुविधाएं अंतर्निहित की गई हैं। इस तकनीकी अपग्रेडेशन का परिणाम यह हुआ है कि जहां एक तरफ पारदर्शी और सही तरीके से काम करने वाले एनजीओ को त्वरित और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के डिजिटल मंजूरी मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ वास्तविक समय में फंड ट्रैकिंग की व्यवस्था लागू होने से देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में लिप्त या संदिग्ध खातों और विदेशी स्रोतों पर चौबीसों घंटे पैनी नजर

रखना बेहद आसान हो गया है। सरकार द्वारा उठाए गए इन सख्त कदमों और विनियामक कड़ाई के औचित्य को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के माध्यम से बेहद स्पष्टता से समझा जा सकता है। ये आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि सरकार की नीति का उद्देश्य किसी भी वैध सामाजिक संस्था को परेशान करना नहीं, बल्कि वित्तीय जवाबदेही की एक ऐसी अचूक प्रणाली स्थापित करना है जिससे देश की सुरक्षा अभेद्य रहे। आधिकारिक सरकारी डेटा के अनुसार, साल 2012 से लेकर अब तक देश भर में कुल 52,159 संस्थाओं को विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए एफसीआरए लाइसेंस जारी किए गए थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में किए गए कड़े वित्तीय ऑडिट, वार्षिक रिटर्न की सघन जांच और नियमों के अनुपालन के कठोर मापदंडों के लागू होने के बाद, वर्तमान में देश भर में केवल 14,455 एनजीओ ही सक्रिय बचे हैं-यानी मूल रूप से पंजीकृत संस्थाओं में से केवल करीब 28 प्रतिशत संगठन ही वर्तमान में वैध रूप से विदेशी चंदा पाने और उसका उपयोग करने की पात्रता रखते हैं। गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड और आधिकारिक आंकड़ों के विस्तृत विश्लेषण से यह साफ होता है कि अब तक लगभग 22,498 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस सीधे तौर पर नियमों के गंभीर उल्लंघन के कारण रद्द किए जा चुके हैं, जबकि 15,206 से अधिक अन्य लाइसेंसों की अवधि उनके समय पर रिन्यूअल न होने या विनियामक कमियों के कारण स्वतः समाप्त (Deemed E&pired) मान ली गई है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में संसद और सार्वजनिक मंचों पर देश के सामने यह स्थिति स्पष्ट की है कि लाइसेंस रद्द होने या समाप्त होने का एकमात्र कारण वित्तीय धोखाधड़ी ही नहीं है, बल्कि कई मामलों में संगठनों द्वारा बुनियादी नियमों का पालन न करना रहा है, जैसे लगातार कई वर्षों तक अपना अनिवार्य वार्षिक रिटर्न दाखिल न करना, निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने लाइसेंस का नवीनीकरण न कराना या कानूनन अनिवार्य किए गए बैंक खातों को सक्रिय न रखना। इसके साथ ही, विनियामक तंत्र को केवल सक्रिय और वास्तविक काम करने वाले संगठनों तक सीमित रखने के लिए नई व्यवस्था के तहत यह अनिवार्य कर दिया गया है कि कोई भी एनजीओ अपने लाइसेंस के रिन्यूअल का दावा तभी कर सकेगा जब वह पिछले दो वित्तीय वर्षों के भीतर समाज कल्याण के कार्यों में कम से कम 10 लाख का वास्तविक और प्रमाणित प्रोजेक्ट खर्च दिखाना अनिवार्य है। इस व्यवस्था से केवल कागजों पर चलने वाले, निष्क्रिय या 'शेल संगठनों' को स्वतः इस वित्तीय तंत्र से बाहर कर दिया गया है।

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ाव और सांस्कृतिक विविधता के कारण सामरिक दृष्टि से हमेशा से देश के सबसे संवेदनशील हिस्सों में से एक रहा है। इस क्षेत्र में विदेशी शक्तियों द्वारा स्थानीय स्तर पर अलगाववादी प्रवृत्तियों को हवा देने, सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों को वित्तीय मदद पहुंचाने और जनसांख्यिकीय संतुलन को कृत्रिम रूप से प्रभावित करने के प्रयासों का इतिहास रहा है। इस गंभीर सुरक्षा चुनौती को भांपते हुए गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर के राज्यों में सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों की फंडिंग पर विशेष और अत्यधिक कड़ा नियंत्रण स्थापित किया है। आंकड़ों के अनुसार, साल 2010 से लेकर अब तक पूर्वोत्तर के सात प्रमुख राज्यों में कुल 2,313 संगठनों को एफसीआरए के तहत विदेशी चंदा प्राप्त करने की अनुमति या पंजीकरण दिया गया था। लेकिन सरकार द्वारा की गई सुरक्षा जांच, कड़े ऑडिट मानकों और राष्ट्रहित की वेदी पर कसे गए मापदंडों के बाद, वर्तमान में पूर्वोत्तर के इन संवेदनशील राज्यों में केवल 463 संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस ही सक्रिय और वैध बचे हैं। इसका सीधा और स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि पूर्वोत्तर भारत में वर्तमान में लगभग हर पांच में से केवल एक एनजीओ ही विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए कानूनी रूप से पात्र है। सरकार का यह ठोस और सख्त कदम पूर्वोत्तर की आंतरिक सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखने, विदेशी फंडों के अनियंत्रित प्रवाह के माध्यम से होने वाले अवैध सामाजिक व जनसांख्यिकीय बदलावों को पूरी तरह रोकने, और इस रणनीतिक भू-भाग को विदेशी ताकतों के किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार या आंतरिक अस्थिरता का केंद्र बनने से बचाने के लिए समय की मांग और एक ऐतिहासिक रूप से अनिवार्य दूरदर्शी फैसला साबित हुआ है।

प्रशासनिक स्तर पर उठाए गए इन कदमों को एक मजबूत विधायी और कानूनी आधार देने के लिए सरकार ने संसद के पटल पर भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 25 मार्च 2026 को भारत की संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में 'विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' आधिकारिक रूप से पेश किया गया। विनियामक कमियों को तुरंत दूर करने और कानून को बिना किसी देरी के लागू करने के लिए गृह मंत्रालय ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए 22 जून 2026 को नए 'एफसीआरए संशोधन नियम, 2026' को देश भर में अधिसूचित कर पूरी तरह प्रभावी कर दिया। इस नए विधायी और विनियामक ढांचे में कुछ ऐसे ऐतिहासिक और दूरगामी प्रावधान शामिल किए गए हैं जो विदेशी धन की जवाबदेही को एक नए स्तर पर ले जाते हैं:

भारत के इस कड़े और पारदर्शी रुख को देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था का भी मजबूत संरक्षण प्राप्त हुआ है। भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टिकोण में इस बात को पूरी तरह स्पष्ट किया है कि भारत के संविधान के तहत नागरिकों को मिलने वाला संघ या संगठन बनाने का अधिकार किसी भी स्थिति में विदेशी धन प्राप्त करने की खुली और अनियंत्रित छूट नहीं देता है। देश की शीर्ष अदालत ने विदेशी धन पर अत्यधिक और अनियंत्रित निर्भरता पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए यह भी रेखांकित किया कि वैश्विक मंचों पर इस प्रकार की निर्भरता देश की एक ऐसी छवि पेश करती है जैसे भारत अपनी आंतरिक आवश्यकताओं और कल्याणकारी कार्यों को स्वयं पूरा करने में सक्षम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की इस न्यायिक टिप्पणी ने सरकार के इस रुख को पूरी तरह सही ठहराया है कि विदेशी पूंजी का देश में प्रवेश कोई मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक ऐसा विषय है जो पूर्ण रूप से राज्य के कड़े नियमन और राष्ट्रीय सुरक्षा के अधीन आता है।

किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। भारत सरकार द्वारा एफसीआरए के क्षेत्र में की गई यह अभूतपूर्व विनियामक कड़ाई देश के भीतर किसी भी वैध, पारदर्शी और जन-कल्याणकारी कार्यों में जुटे एनजीओ के खिलाफ नहीं है। इसके विपरीत, 'एफसीआरए 2.0 पोर्टल' जैसे अत्याधुनिक डिजिटल और पेपरलेस माध्यमों को अपनाकर सरकार ने देश के कानून सम्मत और ईमानदार संगठनों के लिए काम की राह को और अधिक सुगम, पारदर्शी और मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त बना दिया है। यह कड़ा रुख केवल उन ताकतों और साठगांठ के खिलाफ एक निर्णायक और रणनीतिक युद्ध है जो विदेशी धन की आड़ में देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने, देश विरोधी एजेंडा चलाने और भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। यह संपूर्ण सुधार प्रक्रिया भारत को एक आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और बाहरी हस्तक्षेप से पूरी तरह मुक्त राष्ट्र बनाए रखने की दिशा में मोदी सरकार का एक ऐतिहासिक, दूरदर्शी और राष्ट्रहित में उठाया गया मील का पत्थर साबित हो रहा है।

अशोक भाटिया,
वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार,लेखक,
समीक्षक एवं टिप्पणीकार

आंचलिक

प्रीति माहेश्वरी फिर बनीं धार महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष सहित नेताओं ने दी बधाई

अजय नलवाया (7879800048)
धार ● दैनिक इंदौर संकेत

मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रीना बौरासी सेतिया के नेतृत्व में नवनियुक्त जिलाध्यक्षों की सूची जारी की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की अनुशंसा पर धार जिले की कमान एक बार फिर प्रीति माहेश्वरी को सौंपी गई है। लगातार दूसरी बार जिम्मेदारी मिलने पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। पार्टी ने संगठनात्मक अनुभव और सक्रियता को देखते हुए प्रीति माहेश्वरी पर फिर भरोसा जताया है।

नियुक्ति की घोषणा होते ही धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष स्वतंत्र जोशी, हरदेव सिंह जाट, पूर्व विधायक पांचीलाल मेडा, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष रोहित कामदार, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष कृष्णा पवार सेवादल जिला अध्यक्ष जितेंद्र जोशी प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि अशोक मांझी, सोशल मीडिया विभाग जिला अध्यक्ष प्रिंस ठाकुर सहित जिले के कई कांग्रेसी नेताओं ने प्रीति माहेश्वरी को बधाई दी और उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं।

मंडी शुल्क बढ़ाने के विरोध में उतरे व्यापारी, सरकार से फैसला वापस लेने की मांग

दैनिक इंदौर संकेत

खंडवा ● मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों में मंडी शुल्क 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.5 प्रतिशत करने का विरोध तेज हो गया है। मंगलवार को खंडवा में व्यापार एवं उद्योग कांग्रेस ने पुरानी अनाज मंडी कार्यालय पहुंचकर मंडी सचिव को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मंडी शुल्क में 0.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि मंडी शुल्क बढ़ने से व्यापारियों की लागत बढ़ेगी। इसका असर किसानों और आम उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। संगठन का कहना है कि इस फैसले से मध्यप्रदेश की मंडियां पड़ोसी राज्यों की मंडियों की तुलना में प्रतिस्पर्धा में कमजोर हो सकती हैं। इससे व्यापार प्रभावित होने

की आशंका है। व्यापार एवं उद्योग कांग्रेस के खंडवा शहर अध्यक्ष संदीप सोनी ने कहा कि संगठन व्यापारियों और उद्योग से जुड़े मुद्दों को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने के लिए काम करेगा। उन्होंने बताया कि यह संगठन का पहला सामूहिक कार्यक्रम था, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने सरकार से मंडी शुल्क बढ़ाने का फैसला वापस लेकर पहले की व्यवस्था लागू करने की मांग की। कार्यक्रम में शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी और नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने व्यापारियों की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए, जिनका असर व्यापार, कृषि और आम लोगों पर पड़े। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने 'देश का कल्चर-एग्रीकल्चर' के नारे भी लगाए।

ज्ञापन में यह मांग रखी

व्यापारियों ने ज्ञापन में मांग की कि मंडी शुल्क में की गई 0.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी तत्काल वापस ली जाए। साथ ही किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए पहले की शुल्क व्यवस्था फिर से लागू की जाए।

नर्मदा नदी में डूबीं दो युवतियां, संतुलन बिगड़ने से गहरे पानी में गई

दैनिक इंदौर संकेत

खंडवा ● ओंकारेश्वर में मंगलवार दोपहर मुंबई से भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करने आईं दो युवतियां, सृष्टि और सेजल स्नान के दौरान अचानक गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं। मौके पर मौजूद नाविक मुकेश वर्मा और स्थानीय युवाओं की तत्परता से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

दोपहर में स्नान के दौरान गहरे पानी में गईं युवतियां

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना दोपहर करीब 3:50 बजे की है। दोनों युवतियां नर्मदा नदी में स्नान कर रही थीं, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गहरे पानी में समाने लगीं। युवतियों को डूबता देख नाविक मुकेश वर्मा ने बिना देरी किए नदी में छलांग लगा दी। नाविक ने स्थानीय युवाओं की मदद से दोनों युवतियों को सकुशल बाहर निकाला। नाविक मुकेश पूर्व में भी कई श्रद्धालुओं की जान बचा चुके हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कर चुका है।

श्रद्धालुओं से सुरक्षा नियमों के पालन की अपील

हादसे के बाद प्रशासन ने श्रद्धालुओं से नर्मदा घाटों पर सतर्क रहने और गहरे पानी में न जाने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि श्रद्धालु सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय लोगों द्वारा दी जा रही चेतावनियों का पालन करें और निर्धारित सीमा से आगे न जाएं।

नागेश्वर पालकी यात्रा में नहीं बजेगा डीजे, शांति समिति की बैठक में फैसला

दैनिक इंदौर संकेत

बड़वाह ● पुलिस थाने में मंगलवार को शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान आगामी सावन माह, कावड़ यात्रा, आदिवासी दिवस, रक्षाबंधन और मिलादुन्नबी जैसे प्रमुख त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्द्रपूर्ण माहौल में संपन्न कराने पर मंथन हुआ। लगभग एक घंटे चली इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नगर के कई लोग शामिल हुए। बैठक में नगर के अधिष्ठाता देव भगवान नागेश्वर की पालकी यात्रा की व्यवस्थाओं पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। नगर हिंदू संगठन के अध्यक्ष रवि जैन ने बताया कि इस बार पालकी यात्रा में डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यात्रा में स्थानीय कलाकार, बैंड-बाजे, सुंदरकांड मंडलियां और महिला मंडली भजन-कीर्तन करते हुए शामिल होंगी। इसके अलावा समिति सदस्यों ने हाईवे पर ट्रैफिक डायवर्जन, यात्रा मार्ग से अतिक्रमण हटाने और बिजली सप्लाई की मांग रखी। विश्व हिंदू परिषद के रितेश कौशल ने सावन महीने में खुले में बिक रही नॉनवेज की दुकानों को बंद कराने की मांग की, जिस पर अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसडीओपी अर्चना रावत, टीआई राजेंद्र बर्मन और तहसीलदार ने कहा कि कोई भी जुलूस निकालने से पहले पुलिस को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा ताकि सुरक्षा,यातायात व्यवस्था सही रखी जा सके।

बलवाड़ी-दुगानी मार्ग पर 3 फीट तक भरा पानी, छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित

दैनिक इंदौर संकेत

खरगोन ● वरला तहसील में बलवाड़ी-दुगानी मार्ग पर अरुणावती नदी के पास मुख्य सड़क पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से लंबे समय से जलभराव बना हुआ है। करीब 20 फीट चौड़े और 3 फीट गहरे हिस्से में पानी भरा रहने से आवागमन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल जल निकासी और सड़क की मरम्मत की मांग की है।

इस जलभराव से वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय जनजातीय सीनियर कन्या छात्रावास, बलवाड़ी (दूधखेड़ा) की 50 से अधिक छात्राओं के अलावा आसपास के ग्रामीण विद्यार्थी, किसान, व्यापारी और अन्य राहगीर प्रभावित हो रहे हैं। सड़क से गुजरते समय वाहनों से उड़ने वाले कीचड़ और गंदे पानी के छींटों से छात्राओं की यूनिफॉर्म खराब हो जाती है। ग्रामीणों के अनुसार, कई बार छात्राओं को कपड़े बदलने के लिए छात्रावास या घर लौटना पड़ता है। इससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। वहीं, सड़क पर लगातार पानी भरे रहने से फिसलन बढ़ गई है, जिससे दोपहिया वाहन चालक और पैदल राहगीर अक्सर

गिरकर चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जल निकासी की समस्या से लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। बारिश का पानी सड़क पर जमा होने से हर साल यह समस्या और गंभीर हो जाती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल निकासी की स्थायी व्यवस्था और क्षतिग्रस्त सड़क की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है। ग्रामीण सतीश पवार, संजय सोलंकी, कैलाश कास्ट सहित अन्य लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो छात्राओं और ग्रामीणों के साथ आंदोलन किया जाएगा। उनका कहना है कि किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी संबंधित विभाग और प्रशासन की होगी।

28 अगस्त से यूएई में हो सकता है महिला एशिया कप

नई दिल्ली (एजेंसी) ● महिला एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर के बीच संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में खेले जाने की संभावना है। हालांकि एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) ने अभी तक आठ टीमों वाले इस टूर्नामेंट का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन सभी भाग लेने वाले देशों से इन तारीख़ों को ध्यान में रखने के लिए अनौपचारिक रूप से कहा गया है। यह महिला टी 20 एशिया कप का छठा संस्करण होगा। इसमें मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के अलावा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, मलेशिया, थाईलैंड और मेज़बान यूएई हिस्सा लेंगे। अभी कार्यक्रम, तारीख़ों और मेज़बान स्थल की घोषणा इसलिए नहीं कर पाया है क्योंकि उसे अपने शीर्ष नेतृत्व से अंतिम मंजूरी का इंतज़ार है। फ़िलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी एसीसी के भी अध्यक्ष हैं। 22 जुलाई को टीमों को भेजे गए एक ईमेल में एसीसी ने टूर्नामेंट का लोगो साझा करते हुए बताया था कि आयोजन स्थल 'फ़िलहाल तय किया जा रहा है।' साथ ही टीमों से 27 अगस्त तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई थी और फ़ाइनल 13 सितंबर को प्रस्तावित रखा गया था। बताया जा रहा है कि भाग लेने वाले देश यात्रा और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए एसीसी से कार्यक्रम का इंतज़ार कर रहे हैं। बीसीसीआई ने महिला एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी थी, लेकिन बाद में उसे हटा लिया क्योंकि एसीसी ने अभी तक टूर्नामेंट की आधिकारिक घोषणा नहीं की थी। गौरतलब है कि 2026 एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता 17 से 24 सितंबर के बीच जापान के नागोया में आयोजित होगी।

जूनियर एशिया कप की तैयारियों के लिए भारत में आठ मैच खेलेगी मलेशियाई हॉकी टीम

बेंगलुरु (एजेंसी) ● आगामी जूनियर एशिया कप 2026 की तैयारियों के लिए मलेशियाई अंडर-21 पुरुष हॉकी टीम भारत दौरे पर है। इस दौरे में मलेशियाई टीम भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम और साई टीम से कुल आठ मुकाबले खेलेगी। ये सभी मैच साई नेताजी सुभाष सदर्न सेंटर में आयोजित किए जाएंगे। इस सीरीज दोनों देशों की टीमों को एशिया कप के साथ ही भविष्य के अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों, विशेष रूप से जूनियर एशिया कप, की तैयारी का भी अवसर मिलेगा। इस दौरे का लक्ष्य खिलाड़ियों को उच्च-स्तरीय अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का अनुभव करना और भारत व मलेशिया के बीच मौजूदा खेल संबंधों को और बेहतर बनाना है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच फ्रेडरिक सोयेज ने कहा है कि इस सीरीज से टीम को काफी लाभ होगा। उनके अनुसार ये मुकाबले जूनियर एशिया कप की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे।

अर्शदीप दलीप ट्रॉफी में दिखाएंगे दम नॉर्थ जोन स्क्वॉड का ऐलान

नई दिल्ली (एजेंसी) ● गेंदबाज अर्शदीप सिंह को 23 अगस्त से शुरू होने वाली दलीप ट्रॉफी के लिए जम्मू-कश्मीर के विकेटकीपर कन्हैया वधावन की अगवाई वाली नॉर्थ जोन की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। सीमित ओवरों के विशेषज्ञ अर्शदीप को 2025 में इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में जगह मिली थी, लेकिन चोट और टीम संयोजन के कारण वह टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण नहीं कर सके थे। हाल में भारतीय टेस्ट टीम से बाहर हुए हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को भी उत्तर क्षेत्र की टीम में शामिल किया गया है। जम्मू-कश्मीर की ऐतिहासिक रणजी ट्रॉफी जीत के बाद चयनकर्ताओं ने वहां के छह खिलाड़ियों को टीम में जगह देकर उनके प्रदर्शन को सम्मान दिया है। वधावन के अलावा सलामी बल्लेबाज कामरान इकबाल, हरफनमौला अब्दुल समद, बाएं हाथ के स्पिनर आबिद मुश्ताक, तेज गेंदबाज सुनील कुमार और युधवीर सिंह को भी टीम में शामिल किया गया है। दिल्ली के आयुष बदोनी को उपकप्तान बनाया गया है।

मिर्जापुर: दि मूवी का पहला गाना 'दो नंबरी' रिलीज

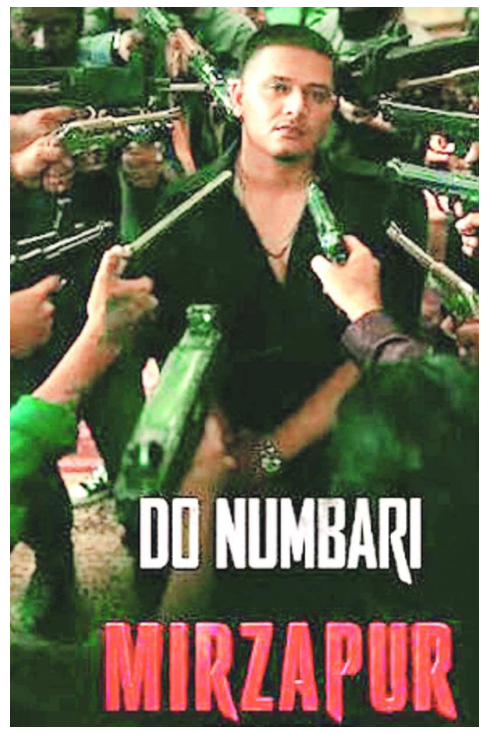

मुंबई (एजेंसी) ● फिल्म मिर्जापुर: दि मूवी का पहला गीत दो नंबरी सोमवार को रिलीज कर दिया गया। इस गाने को हरियाणवी रैपर धांडा न्योलीवाला ने गाया, लिखा और संगीतबद्ध किया है। इसके साथ ही उन्होंने बॉलीवुड में अपने संगीत करियर की शुरुआत भी की है। दमदार हरियाणवी बीट्स और ऊर्जावान अंदाज से सजा दो नंबरी फिल्म की अपराध, सत्ता संघर्ष और दबंगई से भरी दुनिया की झलक पेश करता है। मेकर्स का कहना है कि यह गीत फिल्म के माहौल और किरदारों की बेबाक छवि को प्रभावी ढंग से सामने लाता है। मेकर्स ने बताया कि फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर 11 अगस्त को जारी किया जाएगा। इससे पहले रिलीज हुए टीजर को दर्शकों का अच्छा प्रतिसाद मिला था, जिसके बाद फिल्म को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। मिर्जापुर: दि मूवी लोकप्रिय वेब सीरीज मिर्जापुर की कहानी को पहली बार बड़े पर्दे पर लेकर आ रही है। फिल्म में अली फज़ल, पंकज त्रिपाठी और दिव्येंदु मुख्य भूमिकाओं में हैं। इनके अलावा अभिषेक बनर्जी, रसिका दुगल, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौर, श्वेता त्रिपाठी और सोनल एस चौहान भी अहम किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है, जबकि इसकी कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है। रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले इसका निर्माण किया है। कासिम जगमगिया और विशाल रामचंदानी सह-निर्माता हैं। फिल्म 4 सितंबर, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

बरखा सिंह ने 'वी गॉट यू गर्ल' के सेट पर मनाया बर्थ-डे

मुंबई (एजेंसी) ● अभिनेत्री बरखा सिंह ने अपना जन्मदिन किसी अवकाश या निजी जश्न के बजाय काम के प्रति अपने समर्पण के साथ मनाते हुए अमेजन प्राइम वीडियो के आगामी रियलिटी शो 'वी गॉट यू गर्ल' के सेट पर बिताया। क्रिमिनल जस्टिस 4 और दि सबरमती रिपोर्ट में अपने अभिनय से पहचान बना चुकी बर्खा इन दिनों अमेजन प्राइम वीडियो के बहुप्रतीक्षित रियलिटी शो वी गॉट यू गर्ल की शूटिंग में व्यस्त हैं। इसी दौरान उन्होंने अपना जन्मदिन भी सेट पर मनाया। बताया गया है कि इस महीने रिलीज़ होने वाला यह शो बरखा के करियर का एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। डिजिटल मनोरंजन जगत में अपनी अलग पहचान बना चुकी बर्खा इस शो के जरिए दर्शकों के सामने एक नए अंदाज़ में नजर आएंगी। हालांकि शो की कहानी और प्रारूप को लेकर फिलहाल अधिक जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन इसके ऊर्जावान और नए फॉर्मेट को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। अपने कार्यरत जन्मदिन पर बरखा सिंह ने कहा कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि असली निरंतरता खास मौकों पर नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के काम में बनती है। इसलिए अपने जन्मदिन पर सेट पर होना मेरे लिए बिल्कुल स्वाभाविक है। हर दिन कुछ नया सीखना, टीम के साथ मिलकर काम करना और हर प्रोजेक्ट के साथ खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करना मुझे बेहद संतुष्टि देता है। आज मैं उन सभी मौकों के लिए दिल से आभारी हूं जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया। आगे भी मैं एक कलाकार के तौर पर खुद को और दर्शकों दोनों को नए-नए अंदाज़ में चौंकाती रहना चाहती हूं। बर्खा सिंह जल्द ही बहुप्रतीक्षित क्राइम थ्रिलर टैक्स डिपार्टमेंट स्टोरी में एक आईआरएस अधिकारी की भूमिका निभाती नजर आएंगी। यह किरदार उनकी अब तक की गर्ल नेक्स्ट डोर छवि से अलग माना जा रहा है और दर्शकों को उनका नया अभिनय रूप देखने को मिलेगा।

उज्जैन संभाग

भगवान श्री महाकालेश्वर को कांवड़ियों ने किया जल अर्पण

मंदिर की व्यवस्थाओं की कांवड़ समितियों ने की सराहना

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन ● श्रावण-भादौ मास 2026 के अंतर्गत भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार विभिन्न कांवड़ समितियों द्वारा भगवान श्री महाकालेश्वर का जलाभिषेक एवं जल अर्पण किया गया। मंदिर प्रबंध समिति द्वारा पूर्व निर्धारित समयानुसार सभी कांवड़ यात्रियों के सुगम प्रवेश, दर्शन एवं जल अर्पण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इस अवसर पर बड़ौदा कांवड़ संघ के तथा कांवड़ यात्रा शिवपुरा खेड़ा, तहसील सांवेर सहित विभिन्न कांवड़ समितियों के श्रद्धालुओं ने श्रद्धा एवं भक्तिभाव के साथ भगवान श्री महाकालेश्वर को सभा मंडप स्थित जलपात्र के माध्यम जल अर्पित किया। कांवड़ समितियों के पदाधिकारियों एवं श्रद्धालुओं ने श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा की गई सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रवेश, जल अर्पण, दर्शन, सुरक्षा, बैरिकेडिंग, पेयजल, मार्गदर्शन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ अत्यंत सुव्यवस्थित एवं श्रद्धालु-अनुकूल रहीं, जिससे सभी कांवड़ यात्रियों को बिना किसी असुविधा के भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन एवं जल अर्पण का सौभाग्य प्राप्त हुआ।श्रावण-भादौ मास के दौरान अत्यधिक संख्या में कावड़ यात्रियों का आगमन होना निर्धारित रहता है। उक्त आगंतुक कावड़ यात्रियों की जल अर्पण की व्यवस्था के लिए सप्ताह में 4 दिवस मंगलवार, बुधवार, गुरूवार, शुक्रवार की गई है। कावड़ यात्री दल को द्वार नंबर 1 एवं हरसिद्धि - चौराहा स्थित विशेष दर्शन मार्ग से प्रवेश दिया जावेगा।

जिला स्तरीय मध्यप्रदेश पर्यटन क्विज 7 को

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन ● मध्यप्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2026 का जिला स्तरीय आयोजन 7 अगस्त को शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, माधव नगर के अटल सभागृह में होगा। जिला स्तर पर प्रथम आने वाली टीम को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। यह प्रतियोगिता पर्यटन और संवर्धन के उद्देश्य से 2016 से हर साल आयोजित की जा रही है। इस बार कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी भाग लेंगे। इसमें शासकीय और अशासकीय स्कूलों के साथ एमपी बोर्ड, सीबीएसई, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय शामिल होंगे। प्रत्येक स्कूल से तीन विद्यार्थियों की टीम बनाई गई है। 112 विद्यालयों का ऑनलाइन पंजीयन पूरा हो चुका है। प्रतियोगिता दो चरणों में होगी। पहले चरण में लगभग 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा होगी। इसके आधार पर शीर्ष 6 टीमों का चयन होगा। दूसरे चरण में ऑडियो-वीडियो राउंड होगा।

वन विहार में मनोरंजक गतिविधियां कराई, विजेताओं को पुरस्कृत किया

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन ● भारत विकास परिषद महाकाल शाखा का वन विहार कार्यक्रम चिंतामण स्थित निजी गार्डन में हुआ। शाखा के संस्थापक दीपक राजवानी के अनुसार आयोजन अध्यक्ष रवि मूले, सचिव अशोक अग्रवाल और कोषाध्यक्ष यशी सिंह के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में बच्चों के खेल, कपल गेम्स, सावन के झूले और हाउजी सहित कई मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की गईं। विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 55 विजेताओं को संस्था के सदस्यों और पदाधिकारियों ने पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम में प्रांतीय पदाधिकारी नीला टकशाली और राजेश पोरवाल की विशेष उपस्थिति रही। वन विहार के संयोजक अमित घारिया, विजय शाह, रितेश पोरवाल, सविता गुप्ता और ज्योति रत्नावत रहे। संचालन गीता अग्रवाल और मोहन हिंगोले ने किया। सचिव अशोक अग्रवाल ने आभार व्यक्त किया।

खरीफ फसल 12 करोड़ रुपए का क्लेम मंजूर

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन ● फसल बीमा प्रीमियम चुकाने वाले कुछ किसानों के लिए राहतभरी खबर है। फसल नुकसानी के समय शिकायत दर्ज करने वाले किसानों को कंपनी अब क्लेम देगी। जिले के 74 हलकों के लिए बीमा कंपनी ने 12 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बीमा कंपनी इफको टोकियो के जिला समन्वयक भगवान सिंह ने बताया कि पिछले साल खरीफ-2025 में कुछ किसानों की फसलें खराब हुई थी। जिनकी सैटेलाइट रिपोर्ट के आधार पर कंपनी ने किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम मंजूर किया है। कुल 74 हलकों के प्रभावित किसानों को 12 करोड़ रुपए की क्लेम राशि मिलेगी। जल्द ही राशि किसानों के खाते में जमा होना शुरू हो जाएगी। इधर, क्लेम को लेकर किसान संतुष्ट नहीं है। तर्क हैं कि नुकसान के मुताबिक क्लेम काफी कम है। फसल नुकसान के बाद भी कई किसानों को क्लेम का फायदा नहीं मिल पा रहा है।

बारिश से सड़कें हुईं जलमग्न, कई इलाकों में लगा जाम दिन और रात के तापमान में साढ़े पांच डिग्री का अंतर

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन ● मंगलवार को सुबह करीब 11:30 बजे शुरू हुई तेज बारिश ने पूरे शहर को भिगो दिया। करीब एक घंटे तक हुई तेज बारिश के दौरान कई सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई। इसके चलते नीलगंगा, देवास गेट चौराहा, चामुंडा माता, इंदौर गेट सहित नई सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सुबह से शहर में रुक-रुककर करीब दो घंटे तक बारिश का दौर जारी रहा। बारिश थमने के बाद कई सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई। कुछ ही देर बाद तेज धूप भी निकल आई। वेधशाला के अनुसार, उज्जैन में अब तक 523 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है। शहर में बादलों का डेरा बना हुआ है, लेकिन तेज झमाझम बारिश का लोगों को अभी भी इंतजार है। पिछले दो दिनों से रुक-रुककर हो रही बारिश के चलते दिन और रात के तापमान में महज साढ़े पांच डिग्री का अंतर रह गया है। बीती रात तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार दोपहर यह 24.5 डिग्री सेल्सियस रहा। बारिश के कारण शहर में नीलगंगा, गदा पुलिया, केडी गेट और चामुंडा माता मंदिर के सामने सहित कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे राहगीरों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

पुष्यमित्र भार्गव के बतौर महापौर चार साल

अफसरों से पटरी बैठाना मेरा काम नहीं

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● पुष्यमित्र भार्गव और उनकी निगम परिषद का कार्यकाल चार साल का हो गया है। अब अंतिम एक साल बाकी है। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने मंगलवार को अपने कामों का लेखा-जोखा पेश किया। अपने अहम काम गिनाए और चार साल में पांच निगमायुक्त पर भी बात की।

पुष्यमित्र भार्गव का महापौर पद पर चार साल हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने और निगम ने क्या काम किए और क्या कमी रह गई इस पर मंगलवार को मीडिया से चर्चा की। इसमें कई मुद्दों पर बात की। कमी पर कहा कि भागीरथपुरा की घटना दुखद थी लेकिन इससे काफी कुछ सीखा। केबल कार और स्ट्रीट डॉग की समस्या पर ज्यादा नहीं कर सकें। लेकिन हुकुमचंद मिल का 32 साल पुराना मामला निपटारा, जलूद के लिए देश का पहला ग्रीन बॉण्ड जारी होना, नर्मदा के चौथा चरण 2800 करोड़ को अहम बताया।

क्या बोले पांच निगमायुक्त और ब्यूरोक्रेसी पर : महापौर

भार्गव ने उनके चार साल के कार्यकाल में पांच निगमायुक्त होने और अधिकारियों से पटरी नहीं बैठने पर खुलकर बात रखी। महापौर ने कहा कि मेरा काम अधिकारियों से पटरी बैठाना नहीं था। मेरा काम था जो शहर के लिए बेहतर हो वह करना, उसके लिए नीति तय करना, आगे बढ़ना और इसका पालन मैदान में अधिकारियों को करना है।

राजनीतिक अनुभव पर बोले- मैं अब थोड़ा शातिर हो गया : वहीं भार्गव जब महापौर बने तब राजनीति में उनका पहला कदम था। ऐसे में राजनीतिक अनुभव नहीं होने, राजनीति नहीं आने, शातिरबाजी को लेकर सवाल उठा। इस पर उन्होंने कहा कि मैंने जैसा हूं वैसे ही रहकर काम करने की कोशिश की है। रही शातिरबाजी की बात तो मैं अब थोड़ा शातिर तो हो गया हूं।

इंदौर को भारत सरकार के डिजीपिन प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाला देश का पहला शहर बनाया गया। क्यूआर आधारित डिजिटल पता व्यवस्था लागू की गई।

महापौर ने रिपोर्ट कार्ड में यह बताया

- महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अनंत इंदौर का नाम देते हुए कहा कि चार साल में भविष्य के इंदौर पर काम किया गया है। साल 2047 इंदौर के लिए पानी, सीवरेज, डिजिटल इंदौर और ग्रीन इंदौर कॉन्सेप्ट अहम रहा।
- देश का पहला म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड : इस राशि से जलूद क्षेत्र में 60 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किया गया। इससे हर माह पांच करोड़ बच रहे।
- भविष्य की पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ?2,156.16 करोड़ की लागत से चार मेगा जल प्रदाय परियोजनाओं का कार्य शुरू।
- चार सालों में 122.09 करोड़ की लागत से सात प्रमुख सीवरेज परियोजनाएं पूर्ण हुईं तथा 30.65 किलोमीटर नई सीवर लाइन बिछाई गई।
- शहर की 24 मास्टर प्लान सड़कों पर काम। शहर में 23 फ्लाईओवर का काम चल रहा है।

जिला प्रशासन की अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई

कॉलोनाइजर पर 24 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● इंदौर में अवैध कॉलोनियों के साथ ही अब अवैध खनन पर जिला प्रशासन की सख्ती शुरू हो गई है। अपर कलेक्टर कोर्ट ने अवैध खनन के लिए एक पक्षकार पर 24 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। इंदौर जिला प्रशासन ने कॉलोनी समतलीकरण के नाम पर ली गई खनन मंजूरी का गैरकानूनी खनन में उपयोग करने पर भारी जुर्माना ठोका है। इसमें 24 करोड़ भरने के आदेश हुए हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा के आदेश पर अवैध खनन का केस बना था, जिसमें अपर कलेक्टर रिंकेश वैश्य की कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद यह अर्थदंड का आदेश जारी हुआ।

इन पर लगा दंड

यह दंड सतीश चौधरी पिता मनोहर चौधरी व अमित पारिख पिता राजेंद्र पारिख पर लगा है। इनके द्वारा रिंगनोदिया गांव (सांवेर तहसील) के सर्वे नंबर 213/1/1

की 4.171 हेक्टेयर पर मुरम खनन की मंजूरी ली थी। यह मंजूरी कॉलोनी समतलीकरण के लिए थी। इसमें 30 हजार क्यूबिक मीटर की ही मंजूरी थी लेकिन 80 हजार क्यूबिक मीटर खोद दिया। खनन केंद्रीय जेल के पीछे की ओर तय सीमा से अधिक में हुआ।

इसमें सभी पक्षकारों के बयान हुए। इसके बाद खनिज विभाग का प्रतिवेदन सही पाया गया और इस पर 24 करोड़ की पेनल्टी का आदेश जारी हुआ।

इधर दो करोड़ की पेनल्टी भी लगी

इसी तरह माचला गांव तहसील राउ में भी गोपीचंद पिता छोटेलाल, चंपाबाई, राजेश जिराती, सुधीर चौधरी पर अवैध खनन का केस बना। इसमें सर्वे नंबर 248/49 की 1.336 हेक्टेयर जमीन पर अवैध खनन किया गया। इस पर दो करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है।

कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए 14 वर्ष की आयु अनिवार्यता में राहत

सैकड़ों मिलेगा सीधा लाभ, तकनीकी परेशानियों से मिलेगी राहत

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए 14 वर्ष की न्यूनतम आयु की अनिवार्यता से परेशान विद्यार्थियों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए इस नियम को शिथिल कर दिया है। नए निर्णय के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु होने के कारण जिन विद्यार्थियों को केवल अस्थायी (प्रोविजनल) प्रवेश मिला था, उनका प्रवेश अब नियमित माना जाएगा। साथ ही बोर्ड के पोर्टल पर उनका नामांकन भी किया जा सकेगा।

मार्च में जारी परीक्षा मार्गदर्शिका में कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए 1 जुलाई तक न्यूनतम 14 वर्ष आयु होना अनिवार्य किया गया था। नियम लागू होने के बाद जिले के सैकड़ों विद्यार्थी प्रवेश और नामांकन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे थे। कई स्कूलों ने ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश देने से भी इनकार कर दिया था। अभिभावकों द्वारा लगातार नियम में राहत की मांग की जा रही थी। अब आयु संबंधी शर्त में छूट दिए जाने के बाद विद्यार्थियों के नामांकन और आगामी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से जिले के सैकड़ों विद्यार्थियों को सीधा लाभमिलेगा और स्कूलों को भी प्रवेश एवं नामांकन संबंधी तकनीकी परेशानियों से राहत मिलेगी।

नोटिस के साथ मान्यता निरस्त करने की भी होगी कार्यवाही

निजी स्कूलों के लिए नई गाइड लाइन तय, नियमों का पालन नहीं तो लगेगा 2 लाख तक जुर्माना

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल ● निजी हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना, मान्यता, नवीनीकरण, मान्यता विस्तार, संकाय वृद्धि, माध्यम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन तथा नाम परिवर्तन को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने नई गाइड लाइन जारी की है। जिसके अनुसार अब विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, शिक्षक व्यवस्था, आईसीटी, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और सुरक्षा निधि जैसे प्रावधानों को भी अनिवार्य किया गया है। अगर किसी निजी विद्यालय द्वारा सरकार की शर्तों का पालन नहीं किया गया तो नोटिस देने की कार्रवाई के साथ मान्यता निरस्त करने और दो लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने की

कार्रवाई की जा सकेगी। मान्यता या नवीनीकरण के लिए छात्र संख्या के आधार पर सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी। नई व्यवस्था में राज्य स्तर पर एक राज्य मान्यता समिति गठित की जाएगी। कम से कम तीन सदस्यों वाली यह समिति निजी विद्यालयों की मान्यता, नवीनीकरण, विस्तार, संकाय वृद्धि, स्थान एवं नाम परिवर्तन जैसे मामलों के लिए नीति, दिशा-निर्देश और निर्णय लेने का कार्य करेगी। समिति में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय और माध्यमिक शिक्षा मंडल के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

45 दिनों के भीतर आवेदन पर अंतिम निर्णय-विद्यालयों को मान्यता अथवा नवीनीकरण के लि तय दस्तावेजों सहित ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। हर वर्ष 30 सितंबर तक मिले आवेदन उसी शैक्षणिक सत्र के लिए विचार किए जाएंगे। इसके बाद आने वाले आवेदन अगल सत्र के लिए मान्य होंगे। बिना नई मान्यता प्राप्त किए विद्यालय नई शाखा संचालित नहीं कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित अधिकारी 45 दिनों के भीतर आवेदन पर अंतिम निर्णय लेंगे। यदि आवेदन अधूरा होगा तो 15 दिनों के भीतर गलतियो की सूचना दी जाएगी तथा आवेदक को तय समय में संशोधित आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

30 करोड़ की शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाया

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेशभर में शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने एवं भूमाफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत इंदौर जिला प्रशासन ने आज मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में की गई इस बड़ी कार्रवाई में राजस्व, पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम ने ग्राम पिपलिया राव स्थित सर्वे नंबर 82 की लगभग 2 एकड़ बेशक़ीमती शासकीय भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान प्रारंभिक अवस्था में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया तथा मौके पर संचालित आटा बनाने का प्लांट भी हटाया गया। एसडीएम जूनी इंदौर घनश्याम धनगर ने बताया कि निर्भय पिता भेरू सिंह एवं लालू नागर ने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर उसके एक हिस्से में प्लॉटिंग कर भूखंडों का विक्रय भी प्रारंभ कर दिया था।

यूडायस के फेर में फंसे 75 से अधिक निजी स्कूल, हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में

मान्यता मिलने के बाद भी यूडायस नंबर नहीं, प्रोफाइल नहीं बनने से प्रवेश और शैक्षणिक रिकॉर्ड पर संकट

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● इंदौर में निजी स्कूलों को मान्यता मिलने के बावजूद यूडायस (यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन) नंबर नहीं मिलने से बड़ी प्रशासनिक उलझन पैदा हो गई है। जिले के 75 से अधिक निजी स्कूल इस समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके कारण इन स्कूलों में प्रवेश लेने वाले हजारों विद्यार्थियों की ऑनलाइन प्रोफाइल नहीं बन पा रही है।

जानकारी के अनुसार पहले स्कूलों को यूडायस नंबर प्राप्त करने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान थी, लेकिन अब यूडायस नंबर जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह केंद्र सरकार के स्तर पर होने लगी है। इसी कारण मान्यता प्राप्त कई नए स्कूलों को अब तक यूडायस कोड आवंटित नहीं हो सका है।

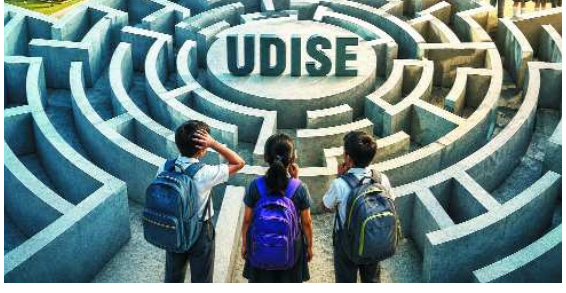

टीसी तो मिल गई, लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं हो रहा अपडेट-सबसे बड़ी समस्या उन विद्यार्थियों के सामने खड़ी हो गई है, जिन्होंने पुराने स्कूल से स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (टीसी) लेकर नए स्कूल में प्रवेश लिया है। पुराने स्कूल के यूडायस पोर्टल से विद्यार्थियों का रिकॉर्ड हट नहीं पा रहा है, जबकि नए स्कूल के पास यूडायस नंबर ही नहीं है। ऐसे में विद्यार्थियों की नई प्रोफाइल तैयार नहीं हो पा रही है और उनका शैक्षणिक रिकॉर्ड बीच में अटक गया है।

समाधान की मांग-शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने मांग की है कि केंद्र और राज्य स्तर पर समन्वय स्थापित कर मान्यता प्राप्त स्कूलों को शीघ्र यूडायस नंबर जारी किए जाएं। साथ ही, जब तक नए स्कूलों को यूडायस उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक विद्यार्थियों के रिकॉर्ड स्थानांतरण के लिए कोई अंतरिम व्यवस्था बनाई जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई और शैक्षणिक दस्तावेज प्रभावित न हों।

हजारों विद्यार्थी प्रभावित

शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो हजारों विद्यार्थियों के ऑनलाइन रिकॉर्ड, भविष्य की बोर्ड परीक्षाओं, छात्रवृत्ति, विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा अन्य शैक्षणिक प्रक्रियाओं पर भी असर पड़ सकता है।

स्कूल संचालकों की बढ़ी चिंता

निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि उन्होंने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर मान्यता प्राप्त कर ली है, लेकिन यूडायस नंबर जारी होने में हो रही देरी का खामियाजा विद्यार्थियों और स्कूलों दोनों को भुगतना पड़ रहा है। कई बार संबंधित स्तर पर संपर्क करने के बावजूद स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है।

अरविंदो इंस्टीट्यूट के चेयरमैन व व्यापमं घोटाले में आरोपी रहे डॉ. भंडारी फिर जांच में घिरे

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के फाउंडर चेयरमैन डॉ. विनोद भंडारी एक बार फिर जांच में घिर गए हैं। डॉ. भंडारी व्यापमं के चर्चित मेडिकल घोटाले में भी आरोपी रहे हैं। इस बार इन पर बेनामी तरीके से जमीन खरीदने के आरोप लगे हैं। अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के फाउंडर चेयरमैन डॉ. विनोद भंडारी को लेकर फिर जांच शुरू हुई है। प्रदेश की जांच एजेंसियों के पास इस बार इनके खिलाफ बेनामी तरीके से जमीन खरीदने के आरोप आए हैं। यह जमीन भंवरसला तहसील मल्हारगंज की है। इसमें करीब 50 सर्वे नंबर शामिल हैं, जिसमें लंबी-चौड़ी जमीन है। इसकी कीमत आज 100 करोड़ से ज्यादा है।

यह शिकायत हुई है-शिकायत में इन सभी 50 सर्वे नंबरों की जानकारी दी गई है। साथ ही कहा गया है कि डॉ. विनोद भंडारी द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है। इसमें उनके साथ ही 18 व्यक्ति हैं। इसमें कई बेनामी नाम हैं, जिन्होंने जमीन खरीदी है। ये मुख्य संपत्तियां ग्राम भंवरसला तहसील मल्हारगंज में हैं।

मुख्य तौर पर यह जमीन है-यह जमीन मुख्य तौर पर सर्वे नंबर 14/1/1, 14/2, 15/2, 15/1/3, 159/1/2/1, 158/2 व 3 व 4, 146/1/3, 36/2, 23/2 सहित अन्य हैं। इसमें कुछ जमीन श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट के नाम पर है, तो कहीं पर महक भंडारी, मंजू पति विनोद भंडारी, अभय कुमार, चंद्रकला पोखरना, ममता पोखरना सहित कई नाम हैं।

पीएमटी घोटाले में डॉ. विनोद भंडारी (व्यापमं घोटाला आरोपी डॉ. विनोद भंडारी) पर आरोप लगे कि उन्होंने सीट बेचकर करोड़ों की अवैध कमाई की। इससे उन्होंने अपने व परिजन, करीबियों के नाम पर अचल संपत्ति ली।

24 घंटे में 20 मीटर सुरंग बनाएगी थाईलैंड की टीबीएम

खुदाई के साथ ही तैयार करती जाएगी कंक्रीट की दीवारें, इंदौर में मशीन असेंबल शुरू

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● इंदौर मेट्रो के अंडरग्राउंड सफर की सबसे बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। थाईलैंड से आई टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) अब एक महीने बाद जमीन से करीब 20 मीटर नीचे उतरेगी। अत्याधुनिक मशीन 24 घंटे लगातार काम करेगी और रोजाना करीब 20 मीटर तक सुरंग तैयार करेगी।

खास बात यह है कि टीबीएम सिर्फ खुदाई ही नहीं करेगी, बल्कि आगे बढ़ते हुए सुरंग की मजबूत कंक्रीट की दीवारें भी बनाती जाएगी। इससे निर्माण कार्य तेजी से पूरा होने के साथ सुरंग को सुरक्षित और टिकाऊ बनाने में मदद मिलेगी। मशीन को असेंबल करने का काम करीब एक महीने में पूरा हो जाएगा।

मशीन का वजन करीब 1,000 टन है। असेंबल होने के बाद यह एयरपोर्ट क्षेत्र से खुदाई शुरू करेगी। पहले चरण में एयरपोर्ट से कालानी नगर तक सुरंग तैयार की जाएगी। इसके बाद अगले चरण का काम शुरू होगा। इंदौर में कुल 12 किलोमीटर मेट्रो अंडरग्राउंड रहेगी। पूरे अंडरग्राउंड हिस्से का काम पूरा होने में करीब चार से पांच साल का समय लगने का

अनुमान है।

टनल बोरिंग मशीन एक चलता-फिरता भूमिगत कारखाना है। इसका सबसे आगे का हिस्सा गोलाकार कटर हेड होता है, जो साढ़े छह मीटर का है। इसी हिस्से में लगे मजबूत स्टील कटर लगातार घूमते हुए मिट्टी और चट्टानों को काटते हैं। मशीन आगे बढ़ती रहती है और पीछे सुरंग तैयार होती जाती है। खुदाई के दौरान निकलने वाली मिट्टी और पत्थर मशीन के अंदर लगे सिस्टम और कन्वेयर के जरिए पीछे भेजे जाते हैं। वहां से इन्हें बाहर निकाला जाता है। इससे सुरंग के भीतर मलबा जमा नहीं होता और मशीन बिना रुके आगे बढ़ती रहती है। टीबीएम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह केवल सुरंग नहीं खोदती, बल्कि उसी समय उसकी दीवारें भी तैयार कर देती है। मशीन के भीतर लगे हाइड्रोलिक सिस्टम पहले से तैयार कंक्रीट के सेगमेंट (रिंग) को एक-एक कर जोड़ते चलते हैं। ये रिंग आपस में मिलकर सुरंग की मजबूत गोलाकार दीवार बनाती हैं। यानी मशीन जितनी आगे बढ़ती है, उतनी ही लंबाई में पक्की कंक्रीट की सुरंग भी तैयार होती जाती है। इससे मिट्टी धंसने का खतरा नहीं रहता और निर्माण तेजी से पूरा होता है।

अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए दो समानांतर सुरंगें बनाई जाएंगी। एक सुरंग से ट्रेन शहर की ओर जाएगी, जबकि दूसरी से वापस लौटेगी। दोनों सुरंगें टीबीएम मशीनों की मदद से तैयार होंगी।

मशीन के अंदर ही पूरी इंजीनियरिंग

टीबीएम कई आधुनिक तकनीकों का मेल है। इसमें मैकेनिकल सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, शक्तिशाली मोटर और गियर लगे हैं, जो एक साथ काम करते हैं। सबसे आगे कटर हेड घूमता है, जबकि उसके पीछे मशीन के बाकी हिस्से लगे रहते हैं। पूरा सिस्टम इस तरह तैयार किया गया है कि खुदाई, मलबा हटाने और कंक्रीट रिंग लगाने का काम एक साथ चलता रहे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक : **अक्षय तिवारी** द्वारा मेसर्स डी.बी. कार्प लिमि. 44-45/ए, 50-51/ए, सेक्टर एफ इंडस्ट्रीयल एरिया, सांवेर रोड़, इंदौर (मप्र)- 452008 से मुद्रित एवं 5/6, नार्थ राजमोहल्ला (गुरूद्वारे के सामने), इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। **आरएनआई - एमपीएचआईएन/2021/81650**
सभी विवादों के लिए न्याय क्षेत्र केवल इंदौर रहेगा। समाचार पत्र में व्यक्तिगत नाम से प्रकाशित खबर एवं आलेख के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।